बजट 2023-24: आयकरदाता से लेकर महिला और किसान तक सभी के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना

इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी

वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट

- 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा
- गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा
- इस साल युवाओं को रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ज्यादा
- गरीबों को एक साल और मिलेगा मुफ्त अनाज
- सिगरेट के बढ़ेंगे दाम, मोबाइल-ईवी होंगे सस्ते

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी। सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट है। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। इस साल 9 राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है।

बजट के बाद 3 बड़े मुद्दों पर सीतारमण के बयान

महंगाई: आपने देखा कि महंगाई नीचे आई है। हमने कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान उस पर है। गेंहू को मार्केट में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इससे गेहूं के दाम कम होंगे। रसोई में महंगाई कम होगी। ये एक्शन तो पहले ही हो गया है। महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, इनकम टैक्स में छूट का फायदा उन्हें भी होगा।

रोजगार: 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्रोजेक्ट्स चल रहे है, पैसा इनके लिए दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट्स बिना रोजगार के कैसे पूरे हो सकते हैं।

बजट का मकसद: बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा के लिए योजनाओं और ग्रीन ग्रोथ पर फोकस है।

जानिए बजट में आपके लिए क्या-क्या ऐलान किए गए

1. इनकम टैक्स: 8 साल बाद छूट की सीमा बढ़ी

अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था।

2. क्या सस्ता, क्या महंगा

टीवी सस्ते होंगे। वजह पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5प्र. से घटाकर 2.5प्र. कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। हीरों की कीमतें कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर टैक्स 16प्र. बढ़ाया गया, ये महंगी होगी। चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।

बजट के दौरान गंभीर मुद्दों पर ऐलान के बीच मजेदार लम्हा भी आया। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गईं। फिर बोलीं- सॉरी...सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे।

3. रोजगार

इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास योजना का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोलीं- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।

4. किसान

सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा।

5. इंडस्ट्री-स्टार्टअप

देश के 6 करोड़ से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योग हैं और 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप। इनके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई'एस का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा।

कुछ और बड़े ऐलान

रेलवे: 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 2014 के मुकाबले ये रेल बजट 9 गुना ज्यादा है।

सीनियर सिटीजन्स: सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी।

महिला: सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5प्र. ब्याज मिलेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर: पीएम आवास योजना के बजट में 66प्र. बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एयरो ड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी।

5जी सर्विस: इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।

पर्यावरण: फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाईड्रोडन मिशन। एनर्जी ट्रांजीशन के लिए 35 हजार करोड़। एनवॉरोन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।

डिजिटल इंडिया: बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजिलॉकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।

बजट के सप्तर्षि, वित्त मंत्री ने बताया क्या है सप्तर्षि

वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के सात आधार बताए। इन्हें सप्तर्षि कहा गया है। 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र।

वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस 'जनभागीदारी' के लिए 'सबका साथ, सबका प्रयास' अनिवार्य है।

रेलवे को मिला 2.4 लाख करोड़ का बजट

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया है। रेलवे के लिए इस बार 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। यह 2013-14 बजट से करीब 9 गुना ज्यादा है। 2013 में रेलवे के लिए करीब 63363 करोड़ रुपए के बाजट का प्रावधान किया गया था। यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है।

रेलवे पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बदला है और इसे लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने पर्यटक मार्गों पर एक नए डिजाइन वाले विस्टा डोम एलएचबी कोच को पेश करने की योजना बनाई है। देश में अब ट्रेन को लेटलतीफी का उदाहरण मानने के बाद स्पीड पर जोर दिया जा रहा है। बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है लेकिन अभी सरकार का ज?यादा जोर वंदे भारत को देश के हर प्रमुख रूट तक पहुंचाना है। इसके अलावा सड़क मार्ग से माल ढुलाई पर हो रहे खर्च को भी कम करने पर जोर है। इसके लिए फ्रेट कॉरिडोर के काम को और तेज किया जा सकता है। इसके लिए देश के कई प्रमुख राज्यों में मालगाड़ियां दौड़ाने के लिए पटरियां बिछानी पड़ेंगी।

रेलवे को विस्तार देने के लिए जाहिर है कि इन्फ्रा पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। फ्रेट कॉरिडोर के लिए बिजली की खपत भी बढ़ानी होगी क्योंकि लंबी दूरी की मालगाड़ियों को तेल पर चलाना घाटे का सौदा होगा यानी रेलवे के लिए बिजली के इन्फ्रा को भी तैयार करना होगा। एल्युमीनियम के कोच बनाने पर भी ज्यादा फोकस हो सकता है क्योंकि यह लोहे के कोच से काफी हल्के होते हैं और ज्यादा वजन भी सह सकते हैं। इन्फ्रा पर इस बार 20 फीसदी तक पैसा बढ़ाने की मांग की गई है।

बजट 2023-24 : बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या हुआ महंगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में कुछ चीजों में राहत दी है, यानी कुछ सामान सस्ते हो जाएंगे। जब विदेश से आयातित किचन चिमनी के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल, सरकार ने किचन चिमनी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है।

सस्ता

खिलौने, साइकिल, मोबाइल, एलईडी, कैमरे, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस से जुड़ी चीजें,

महंगा

विदेश से आयातित किचन चिमनी। सिगरेट, विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें, सोना, चांदी, प्लेटिनम।

पीएम मोदी बोले- ये बजट वंचितों को वरीयता देने वाला, समाज के सपनों को पूरा करेगा

मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बजट वंचितों को वरीयता देने वाला, समाज के सपनों को पूरा करेगा। अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले 'विश्वकर्मा' इस देश के निर्माता हैं। पहली बार 'विश्वकर्मा' के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है।

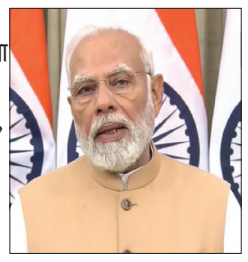

विपक्ष ने कमियां गिनाई हजार, बीजेपी ने खुबियां बताई बेशुमार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया है। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने अच्छी आर्थिक वृद्धि हासिल की है और इसलिए विश्व ने उसे एक आकर्षक स्थल माना है। उन्होंने आम बजट 2023-24 को पिछले बजट की बुनियाद और 'इंडिया एट 100' के मसौदे पर निर्माण की उम्मीद करार दिया। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। सीतारमण जुलाई, 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अपना पांचवां पूर्ण बजट पेश किया। बजट को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने कई सारी खुबियां गिनाई तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसपर सवाल भी उठाए गए।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बल पर अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने की सुविधा:

- ऊर्जा परिवर्तन और शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर प्राथमिक पूंजी निवेश के लिए 35000 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव

- पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और प्रत्युत्तर संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करने के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अधिसूचित किया जाएगा

- पीएम-प्रणाम के माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक 'पंचामृत' तथा निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए 'लाइफ' अथवा पर्यावरण के लिए जीवनशैली की संकल्पना की गई है। यह बजट विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है जो अमृतकाल में हमारा मार्गदर्शन करेगा।

हरित हाइड्रोजन मिशन

वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा 'इससे भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।' श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है।

ऊर्जा परिवर्तन और भंडार परियोजनाएं

वित्तमंत्री ने अपने प्रस्ताव में कहा कि इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4000 एमडब्ल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधीयन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा 'पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।'

नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण

लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी जिसमें 8300 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है।

हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्ताव में बताया कि व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा 'इस कदम से ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।'

पीएम-प्रणाम

'पृथ्वी माता के पुनर्रूद्धार इसके प्रति जागरूकता पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम' राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शरू किया जाएगा।

गोबरधन स्कीम

गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए 'अवशिष्ट से आमदनी' संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या कलस्टर आधारित संयंत्र हैं जिनमें कुल लागत 10000 करोड़ रूपये होगी। मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर करों की कटौती से बचने के लिए जीएसटी का भुगतान किए गए कंप्रेस्ड बायोगैस पर आबकारी शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का सीबीजी अधिदेश यथासमय लाया जाएगा। उन्होंने कहा 'बायो-मास के संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी।'

भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केंद्र

बजट प्रस्ताव की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा 'अगले तीन वर्षों में हम एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे।' उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

मिश्टी

वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में कहा कि वन-रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल मिश्टी की शुरूआत की जाएगी।

अमृत धरोहर

वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में आर्द्रभूमि जैव विविधता का संरक्षण करने वाले स्थानीय समुदायों के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अमृत धरोहर योजना से उनके अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता कार्बन स्टॉक पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उत्तरांचल,उत्तराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रकाशित

सुरत–गुजरात,संस्करण गुरुवार,02 फरवरी–2023 वर्ष–6,अंक–10 पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बजट में नयी कर व्यवस्था चुनने का प्रोत्साहन, सात लाख तक व्यक्तिगत आय कर से मुक्त

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर पांच बड़ी घोषणाएं की हैं। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जिनकी कुल आय सात लाख रुपये तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, जिनकी कुल सालाना आय 7 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें अपने स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान में 5 लाख रुपये तक की आय वाले को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, अब मैं न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा भी न्यू टैक्स रिजीम की ओर टैक्सपेयर्स को आकर्षित करने के लिए इसमें कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा इसमें टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर सात से छह कर दी गई है।

0-3 लाख तक- कोई टैक्स नहीं
3 लाख से- 6 लाख तक-5 प्रतिशत
6 लाख से 9 लाख तक- 10 प्रतिशत
9 लाख से 12 लाख तक- 15 प्रतिशत

12 लाख से 15लाख तक- 20 प्रतिशत
15 लाख से ऊपर- 30 प्रतिशत

सैलरीड क्लास और पेंशनभोगियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ दिया गया है, जो पहले नहीं था। 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये तक का लाभ मिलेगा। वर्तमान में ओल्ड रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है और प्रोफेशनल टैक्स के लिए अधिकतम डिडक्शन 2,500 रुपये है।

सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को फेज वाइज हटाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की घोषणा की है। न्यू टैक्स रिजीम ही अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा और किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करना है तो उसे बदलना होगा। इसके अलावा गैर-सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर टैक्स फ्री लीव इनकैशमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। पांच करोड़ रुपये से अधिक की सालाना इनकम पर सरचार्ज की रेट 37त्न से घटाकर 25त्न कर दी गई है।

पुराने और नए टैक्स रिजीम में क्या अंतर है?

वर्ष 2020 से देश में इनकम टैक्स की दो प्रणाली मौजूद हैं। पहली वाली को ओल्ड टैक्स रिजीम के नाम से जाना जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई थी हालांकि अभी पुरानी टैक्स प्रणाली को भी बरकरार रखा गया है।

ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 C और 80 D जैसे टैक्स सेविंग उपकरणों के जरिए टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कोई इग्जेम्प्शन नहीं है। इस वजह से नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया और इसी वजह से सरकार ने इस बार सारी घोषणाएं इसी के तहत की है। सैलरी पाने वाले लोगों को न्यू टैक्स रिजीम से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80 C और सेक्शन 80 D के तहत मिलने वाली डिडक्शन नहीं मिलती है।

रेलवे का पूंजीगत व्यय 2.4 लाख करोड़ रुपए-आम बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे को वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो वर्ष 2022-24 की तुलना में 65.6 प्रतिशत अधिक तथा वर्ष 2013-14 के आवंटन की तुलना में नौ गुना है। आम बजट 2022-23 में रेलवे को पूंजीगत आवंटन 1.4 लाख करोड़ रुपए था, जबकि राजस्व व्यय 3267 करोड़ रुपए तय किया गया था।

धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई

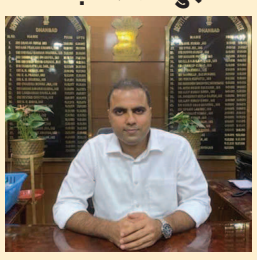

रांची। झारखंड के धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शक्ति मंदिर की बगल में स्थित आशीर्वाद टावर में कल देर शाम आग लग गयी? और जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई।

धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज बताया कि मृतकों में 10 महिला तीन बच्चे और एक पुरुष शामिल है।पुलिस सूत्रों ने बताया कि आग आशीर्वाद ट्विन टावर के पीछे वाले बी ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर लगी थी। दमकल की गाड़ियां रात में ही आग पर काबू पाने की कोशिश में सफल रही।

सूत्रों ने बताया कि शादी के कार्यक्रम के लिए लोग अपार्टमेंट में थे तभी गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई।आग दूसरे तल्ले में चार्टर्ड एकाउंटेंट पंकज अग्रवाल के घर लगी, जो धीरे धीरे तीसरे तल्ले तक फैल गई और इसमें 14 लोगों की मौत हो गई।

इस बीच पीएमओ ने इस बात को लेकर दो ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धनबाद में आग लगने से कई लोगों की मौत की सूचना मिली जिससे मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है।मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धनबाद अग्निकांड में प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ की ओर से दो लाख रुपये दिये जाएंगे जबकि घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

यूपी में शूद्र के सहारे दलितों और पिछड़ों की लामबंदी शुरू

अखिलेश यादव ने राजनीतिक लड़ाई को दिया नया रंग

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा यह कहकर 'मैं शूद्र हूं या नहीं' ने राजनीतिक लड़ाई को नया रंग दे दिया है। इस शब्द के सहारे पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को लामबंद करने की चाहत में सपा मुख्यालय के बाहर मंगलवार को एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि 'गर्व से कहो हम शूद्र हैं।' अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा मुंबई महाराष्ट्र की ओर से लगाए गए इस पोस्टर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने नाम के आगे डॉ. शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल लिखवाया है। इसमें सबसे पहले लिखा गया है जय शूद्र समाज, फिर 6743 जातियां शूद्र समाज लिखा गया है। इस पोस्टर के बाद बहस छिड़ गई है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन कहते हैं कि जब धर्मग्रंथों में लिखा है कि चार प्रमुख वर्ग है, पहला क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य और चौथा शुद्र, तो इसमें शूद्र होने पर गर्व करने में कौन सी दिक्कत है। दरअसल, अखिलेश ने सोमवार को कहा था कि मैं सीएम योगी से पूछना चाहूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं।

अखिलेश यादव ने दिया था ये बयान

रविवार की देर शाम करहल पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वह सदन में सीएम योगी से पूछेंगे कि वे शूद्र हैं या नहीं। कहा कि वे या सपा श्रीराम और श्रीरामचरित मानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन, मानस में जो लिखा है उसे नकारा नहीं जा सकता है। यह सवाल हमारा और आपका नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्या द्वारा की गई रामचरित मानस पर टिप्पणी के सवाल को टाल गए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण अवार्ड को लेकर कहा कि जब लेटर मिल जाएगा तब इस पर बोलेंगे। स्वामी प्रसाद पर मुकदमा दर्ज कराने के सवाल पर कहा कि यह भाजपा है और इसमें कोई भी किसी पर मुकदमा दर्ज करा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- पंजीकृत श्रमिकों में से कितनों के पास राशन कार्ड

नई दिल्ली। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र से यह विवरण देने को कहा कि 28.55 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से कितने के पास राशन कार्ड हैं और क्या उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन का लाभ दिया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने मामले को 20 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पंजीकरण ही इस मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि यह निश्चित है कि केंद्र ने राज्यों के साथ ई-श्रम पोर्टल पर एकत्र किए गए डेटा को साझा किया होगा। कोर्ट ने राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के बारे में डेटा साझा करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित कार्यकर्ताओं को लाभ उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि योजनाओं का उद्देश्य है। अदालत ने टिप्पणी की कि केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अनधिकृत श्रमिकों के लिए बनाई गई योजनाएं उन्हें दी जाती हैं।

शीर्ष अदालत ने मामले को 20 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पंजीकरण ही इस मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि यह निश्चित है कि केंद्र ने राज्यों के साथ ई-श्रम पोर्टल पर एकत्र किए गए डेटा को साझा किया होगा।

कोर्ट ने कहा कि ईश्रम पोर्टल पर मौजूद डेटा का इस्तेमाल अब उनके फायदे के लिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्यों की ओर से वकील पेश नहीं हुए।कोर्ट ने इन राज्यों के वकीलों को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों पर अपने फैसले के अनुपालन से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था।

प्रधानमंत्री , स्पीकर ने असम के मुख्यमंत्री सरमा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, असम के मेहनती मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा जी को जन्मदिन की बधाई। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। श्री मोदी ने सरमा की प्रशंसा भी की और कहा कि वह कई जन-समर्थक पहलों के माध्यम से राज्य को ऊर्जावान रूप से बदल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जी

को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। राज्य और इसके लोगों को आपके सक्षम नेतृत्व और प्रशासन से लाभ हो। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा और लिखा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के सरमा के अथक प्रयासों से असम में शांति और प्रगति सफलतापूर्वक हुई है।

अगली महामारी के लिए तैयार नहीं दुनिया, रेडक्रॉस ने दी संकट की चेतावनी

नई दिल्ली। पूरी दुनिया अगली महामारी के लिए तैयार नहीं है। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसायटीज के अंतर्राष्ट्रीय संघ(आईएफआरसी) ने चेतावनी दी है कि भविष्य में स्वास्थ्य संकट भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित बढ़ती आपदाओं की तरह मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। रेड क्रॉस की ओर से जारी विश्व आपदा रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि कोरोना महामारी के तीन सालों के बाद भी दुनियाभर में मजबूत तैयारियों में गंभीर कमी है। संघ ने कहा है कि अगले संकट के लिए तैयार होने के लिए विश्वास, इक्विटी और स्थानीय कार्रवाई नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण था।

आसपास हो सकती है अगली महामारी

आईएफआरसी के महासचिव, जगन चपगैन ने कहा कि अगली महामारी आसपास हो सकती है। अगर कोविड-19 से मिले अनुभव के बाद भी तैयारियां तेज नहीं की गई तो मुश्किलें होंगी। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया को कई खतरों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस सदी में जलवायु संबंधी आपदा के साथ बीमारी के प्रकोप में वृद्धि हो सकती है। कोरोना इनमें से एक था। खराब मौसम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

गरीबों को ज्यादा नुकसान

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े खतरे पहले से कमजोर लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गरीब इसकी सबसे ज्यादा चपेट में आता हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि देश घरेलू स्वास्थ्य बजट को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत और वैश्विक स्वास्थ्य में कम से कम 15 अरब डॉलर प्रति वर्ष की वृद्धि करें। भारत उन 10 देशों में शामिल है जहां पिछले 2 सालों में सबसे अधिक आपदाएं आई हैं। पिछले दो साल में अमेरिका में 71, इंडोनेशिया में 62, भारत में 46, चीन में 41, कांगो में 27, पाकिस्तान में 25, फिलिपीन्स में 25, मेक्सिको में 23 और कोलंबिया में 22 आपदाएं आई हैं। ये आँकड़े सासल 2020 और 2021 के हैं। आपदाओं में अमेरिका में 1184 लोग, ब्रिटेन में 2559 लोग मारे गए हैं। फ्रांस में 1499 और भारत में 4743 लोगों की मौत हुई है।

अनदेखा की जानेवाली बीमारियों को खत्म करने में मिली बड़ी सफलता

नजरअंदाज कर दी जानेवाली बीमारियों को खत्म करने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज(एनटीडी) पर जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक दुनिया के 47 देशों ने कम से कम एक एनटीडी को समाप्त कर दिया है। आठ देशों को 2022 में कम से कम एक एनटीडी को समाप्त करने का प्रमाण पत्र दिया गया है।

सिर्फ यात्रा निकालने से नहीं चलेगा काम, कांग्रेस को हासिल करने होंगे वोटः रामचंद्र गुहा

नई दिल्ली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा है कि सिर्फ इससे मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो केवल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा बल्कि वोट भी हासिल करने होंगे। उन्होंने कहा कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र को फिर से जिंदा करने के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह केवल मार्च निकालकर नहीं बल्कि मत हासिल करके होगा। गुहा ने यहां अपनी पुस्तक 'इंडिया आफ्टर गांधी' के तीसरे संस्करण के विमोचन के अवसर पर कहा, 'स्वस्थ लोकतंत्र, जिसमें कोई एक पार्टी विपक्ष को न चलाए, जैसा कि भारत ने 1970 के दशक के अंत से 2014 तक देखा है।%

अपनी बात को पुष्ट करने के लिए गुहा ने कहा कि अन्य सभी दलों के बीच वह कांग्रेस ही थी, जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 191 सीट पर आमने-सामने टक्कर दी थी। रामचंद्र गुहा ने कहा कि कांग्रेस को प्रभाव को हम इससे समझ सकते हैं कि देश के 8 से 12 राज्यों में वह पहले या दूसरे नंबर की पार्टी है। गुहा ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके और टीएमसी जैसे दल भाजपा के मुकाबले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नहीं हैं।

क्या एनसीपी, शिवसेना जैसे दलों से कांग्रेस को मिलेगा फायदा

गुहा ने कहा कि 2019 में 191 सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को टक्कर दी थी, जिनमें से 16 पर ही उसे जीत मिली थी। इस तरह की उसकी सफलता की दर महज 8 फीसदी ही थी। यदि गठबंधन दलों की ओर से उसे साथ मिला होता तो फिर कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन कांग्रेस अकेले ही लड़ती दिखी थी। उन्होने कहा कि इस बार कांग्रेस को बिहार में आरजेडी और जेडीयू का साथ मिल सकता है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना साथ आ सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके का समर्थन मिल सकता है। लेकिन अंत में खुद कांग्रेस को ही मजबूत होना होगा ताकि भाजपा को टक्कर दे सके।

राहुली की इमेज एक सक्षम नेता की नहीं, पर भले आदमी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गुहा ने कहा कि सिर्फ मार्च निकालने से ही लक्ष्य हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए जरूरी है कि वोट भी हासिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे खुद को पुनर्जीवित करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ मार्च निकालकर संभव नहीं होगा। इसके लिए वोट भी चाहिए। राहुल की छवि को लेकर गुहा ने कहा कि वह भले आदमी हैं, लेकिन एक सक्षम नेता की इमेज नहीं बना पाए हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

चैंपियन बेटियां

राहुल गांधी की कन्याकुमारी से जम्मू-कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का हासिल देखें तो सर्वप्रथम उन्होंने उस धारणा को तोड़ा है, जिसमें उन्हें एक अगंभीर राजनेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती रही है। सात सितंबर को देश के दक्षिणी सिरे से शुरू हुई करीब चार हजार किमी यात्रा को मौसम की जटिलताओं और भौगोलिक चुनौतियों के बीच अंजाम देने सहज-सरल कार्य नहीं था। रक्त जमाती सर्दी में उनका लगातार टी-शर्ट में रहना कौतूहल का विषय बना रहा है। जिसकी व्याख्या उन्होंने समाज के उन गरीब लोगों के प्रति संवेदना की बात कही, जिनके पास तन ढकने के लिये कपड़े नहीं होते। निस्संदेह राहुल ने इस यात्रा के जरिये शारीरिक व मानसिक सहनशक्ति दर्शायी है। निस्संदेह, 135 दिन चली यात्रा ने राहुल गांधी की एक जुझारू नेता के रूप में छवि गढ़ी। वे लगातार भाजपा व संघ पर हमलावर रहे और देश की बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण की बात करते रहे। कहीं न कहीं देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक संदेश तो गया कि उनके बीच कोई जूझने वाला नेता खड़ा है। वे लगातार इस कथन को खारिज करने का प्रयास करते रहे कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। वहीं वे दूसरी ओर आगामी आम चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी संगठन में प्राणवायु का संचार करने का प्रयास करते रहे। देश के राजनीतिक परिदृश्य में यह बहस आम रही है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा से क्या हासिल हुआ? क्या राहुल पदयात्रा में मिले समर्थन को आगामी चुनावों में वोटों में तब्दील कर पायेंगे ? क्या वे राजग सरकार के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन बना पाएंगे? हालांकि यह भी सत्य है कि विभिन्न राज्यों में सरकार चला रहे विपक्षी दलों के क्षत्रपों का अपेक्षित समर्थन उन्हें यात्रा के दौरान नहीं मिल पाया। कुछ ही विपक्षी दल उनकी यात्रा में शामिल हुए हैं। सवाल यह भी कि क्या इस पदयात्रा के बाद आगामी आम चुनाव में कांग्रेस विपक्ष को नेतृत्व देने की स्थिति में आई है? यहां सवाल यह भी है कि जब भाजपा 2024 के आम चुनावों के लिये बिगुल फूंक चुकी है तो राहुल गांधी क्या मोदी-शाह की महारथ का मुकाबला करने की स्थिति में आए हैं? फिर भी कह सकते हैं कि नागरिकों से सीधा संवाद और उनकी सहानुभूति हासिल करने में राहुल गांधी कुछ कामयाब तो हुए हैं। इसकी वजह यह भी है कि आम आदमी के दैनिक जीवन से जुड़े मुद्दों और समस्याओं को राहुल ने पदयात्रा के दौरान शिद्दत से उठाया है। लेकिन कांग्रेस को यह ध्यान रखना होगा कि स्पष्ट, निर्णायक, व्यावहारिक संगठनात्मक रणनीति के अभाव में राहुल के प्रयासों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती है। भारत जोड़ो यात्रा इस दिशा में प्रयास का एक शुरुआती बिंदु कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में पदयात्रा के समापन पर शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में आयोजित रैली में राहुल ने जिस तरह भावनात्मक संवाद किया, उसने कम से कम कश्मीर के लोगों के दिल को तो जरूर छुआ है। उन्होंने देश की विविधता की संस्कृति के पक्ष में आवाज बुलंद करने का प्रयास भी किया। साथ ही हिंसा के दर्द को महसूस करने की बात भी कही और इसे खत्म करने के लिय व्यावहारिक उपायों पर बल दिया। कट्टरवाद को खारिज करते हुए उन्होंने अहिंसा के पुजारियों की समृद्ध परंपरा का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी का स्मरण किया। भले ही भाजपा राहुल गांधी की यात्रा की सफलता को स्वीकार नहीं कर रही है लेकिन राहुल ने भाजपा के सामने कई चुनौतियां जरूर पैदा की ।

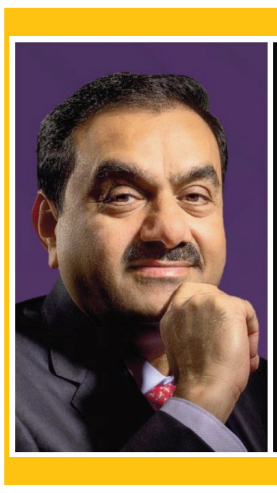

आज का राशिफल

मेष शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

वृषभ पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खान-पान में संतुलन बना कर रखें। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

मिथुन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आय के नये स्त्रोत बनेंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है।

कर्क पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। धन लाभ होगा।

सिंह रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा।

तुला आर्थिक योजना सफल होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

वृश्चिक पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। फिजूलखर्ची से बचें अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन हानि की संभावना है।

मकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

कुम्भ गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। खान पान में संयम रखें। स्वास्थ्य शिथिल रहेगा। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

मीन पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। नेत्र विकार की संभावना है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

हिडनबर्ग रिपोर्ट की सच्चाई सामने आनी चाहिए

जहां तक भारत के राजनेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों का सवाल है तो वे इस तरह के स्कैम के आदि हो चुके हैं। इस लेखक से इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हिंदी दैनिक जन सत्ता के तत्कालीन संपादक स्व. प्रभाष जोशी तक ने एक इंटरव्यू में करीब पैंतीस बरस पहले यहां तक कह दिया था कि अब भारत में भंडा फोड़ पत्रकारिता का कोई असर नहीं होता। जान लें कि ये वो दिन थे जब जन सत्ता को जेहादी पत्रकारिता करने के लिए ख्याति मिली हुई थी। यह बात और है कि उन्हीं दिनों कोलकाता से स्वर्गीय सुरेंद्र प्रताप सिंह के संपादन में हिंदी में रविवार और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार और बाद में एक बार भाजपा सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने एम जे अकबर के संपादन में निकलने वाली संडे मैगजीन कई सरकारों केंद्रीय मंत्रियों अफसरों और रसूखदारों को हिलाया डूलाया था।

(लेखक - नवीन जैन)

अडानी समूह के शेयर घोटाले की तुलना अमेरिका के वाटर गेट काण्ड से की जा रही है। इस काण्ड के उजागर होने के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को अपने पद से त्याग पत्र तक देना पड़ा था लेकिन बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि स्वतंत्र पत्रकारिता के इतिहास में भी यह काण्ड इसलिए नजीर बन गया था कि इस स्कैम का भंडा फोड़ दो अमेरिकी पत्रकारों ने किया था। इनके नाम थे बॉब वुड वर्ड और कॉल बार्स्टिन। बॉब वुड वर्ड को दो बार अंतर्राष्ट्रीय रूप से अति प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम पर करीब तीन साल पहले किताब भी लिखी थी जिसका हिंदी टाइटल था अमेरिका के अब तक के सबसे विवादास्पद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम। अंतिम जानकारी के अनुसार बॉब वुड वर्ड वॉशिंगटन पोस्ट के एसोसिएट एडिटर हैं। जहां तक भारत के राजनेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों का सवाल है तो वे इस तरह के स्कैम के आदि हो चुके हैं। इस लेखक से इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हिंदी दैनिक जन सत्ता के तत्कालीन संपादक स्व. प्रभाष जोशी तक ने एक इंटरव्यू में करीब पैंतीस बरस पहले यहां तक कह दिया था कि अब भारत में भंडा फोड़ पत्रकारिता का कोई असर नहीं होता। जान लें कि ये वो दिन थे जब जन सत्ता को जेहादी पत्रकारिता करने के लिए ख्याति मिली हुई थी। यह बात और है कि उन्हीं दिनों कोलकाता से स्वर्गीय सुरेंद्र प्रताप सिंह के संपादन में हिंदी में रविवार और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार और बाद में एक बार भाजपा सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने एम जे अकबर के संपादन में निकलने वाली संडे मैगजीन कई सरकारों केंद्रीय मंत्रियों अफसरों और रसूखदारों को हिलाया डूलाया था। भारत में तो आज़ादी के बाद से ही घोटाले मशहूर हुए। पहला घोटाला खटारा जीप सप्लाई था जो ब्रिटेन से आयात की गई थीं। तब मीडिया में खबर आम हुई थी कि तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय मेनन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी मित्र थे ने इस सौदे में निजी रुचि दिखाई थी लेकिन कहा गया था कि इस स्कैम के कागज़ात वक्त की हवाओं में इधर उधर बिखर गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में दस साल के कार्यकाल के दौरान तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे घोटालों की झड़ी लग थी और दस से ज्यादा घोटाले हुए लेकिन सब मामले लगभग रफादफा हो गए। हांयह ज़रूर है कि जब देश का पहला हरिदास मूंदड़ा शेयर घोटाला हुआ था तो मुख्य आरोपी हरिदास मूंदड़ा को दो साल की सजा हुई थी। इस घोटाले को पंडित जवाहर लाल नेहरू के दामाद और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के पति सांसद फिरोज गांधी ने संसद में उजागर किया था। नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन वित्त मंत्री स्व. टी टी कृष्णमचारी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संसद में ही अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। हर्षद मेहता शेयर घोटाला तो आज भी काफी चर्चित है। उसे भी सुचेता दलाल नामक इंग्लिश महिला पत्रकार ने उजागर किया था। तब कहा गया था कि सुचेता दलाल को इस स्क्रैम के हीरो हर्षद मेहता ने चुप रहने के लिए करोड़ों की रिश्वत ऑफर की थी। हर्षद मेहता काण्ड इतना चर्चित हुआ था कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम तक हर्षद रख लिए थे। तब हर्षद के ठाठ मुंबई के स्टॉक मार्केट में अमिताभ बच्चन जैसे थे और उनके ऑटो ग्राफ लेने के लिए भीड़ टूटा करती थी। लगभग पचास महंगी कारों के इस मालिक की बाद में जेल में संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई।

जिस हिडन बर्ग एजेंसी ने उक्त कथित भंडाफोड़ किया है बताया जाता है कि उक्त एजेंसी इतिहास में भी ऐसी दूसरी पोल पट्टी भी उजागर करती रही है। मतलब यह कि उक्त कंपनी का यह व्यवसाय है। एक जानकारी के अनुसार कभी हिडनबर्ग निकोला विंस फायनेंस जैसी कंपनियों के भंडा फोड़ में नाम कमा चुकी हैं। इसकी स्थापना एंडरसन नाम के शख्स ने की थी। यह जानना बड़ा रोचक है कि हिडनबर्ग का असली अर्थ होता है एक प्रकार का गुब्बारा या एयरशिप। यह अस्सी किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता था और इसकी कुल लंबाई तीन मीटर थी। चूंकि यह अति ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस से उड़ता था इसलिए इसमें एक बार अमेरिका ने न्यूजर्सी प्रांत में आग लग गई थी। हिडनबर्ग की दो साल की खोजबीन की इस उक्त रिपोर्ट के खिलाफ अडानी समूह ने कुल 413 पन्नों का जवाब जारी किया है जिससे असंतुष्ट होकर हिडनबर्ग का कहना है कि उसने जो भंडाफोड़ किया है उसका बिंदूवार कोई जवाब अडानी समूह ने नहीं दिया है जबकि अडानी समूह के शेयरधारकों में सार्वजनिक बीमा कंपनी उर्फ एलआईसी के आम शेयर धारकों का भी पैसा लगा हुआ है। यह पैसा आम भारतीय आदमी ने अपनी छोटी मोटी बचत करके अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगाया हुआ है। हिडनबर्ग का कहना है कि उसकी दो साल की कड़ी मेहनत से जाहिर हो गया है कि अडानी समूह ने क्रोटी केप्टलिज्म तरीके का इस्तेमाल किया जिसमें भ्रष्टाचार साम दाम दण्ड भेद और हेराफेरी करना आम बात है। जान लें कि अडानी की कुल नेटवर्थ में 1.32 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है जो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार उनकी दौलत का कुल दस फीसद है। जो भी हुआ हो भारत की जनता को दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के गठन की आकांक्षा है क्योंकि भूतकाल में नीरव मोदी विजय माल्या जैसे लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा चूना लगाकर कभी के विदेश चंपत हो चुके है और वहां उनके ठाठ बाठ में कोई कमी नहीं आई है।

पायलट के दौरों ने बढ़ाई गहलोत की धड़कन

(लेखक- रमेश सर्राफ धमोरा)

राजस्थान में सचिन पायलट की लगातार अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बार-बार आश्वासन दे रहा है कि उन्हें उचित मान सम्मान मिलेगा। प्रदेश की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मगर कांग्रेस आलाकमान द्वारा पायलट को ताकतवर बनाने की दिशा में अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पाई है। इससे सचिन पायलट का भी धीरज जवाब देने लगा है। इसीलिए वह एक बार फिर मुखर होकर बयान देने लगे हैं। कुछ दिनों पूर्व सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब में राहुल गांधी से मिलकर राजनीतिक चर्चा की थी। उसके बाद लौटकर उन्होंने राजस्थान में जाट बहुल नागौर हनुमानगढ़ झुंझुनू पाली व जयपुर में बड़ी-बड़ी जनसभाएं कर अप्रत्यक्ष रूप से गहलोत सरकार पर निशाना साध रहें हैं। पायलट की मीटिंगो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहें हैं। हर जगह पायलट ने बेरोजगारों युवाओं किसानों दलितों व पीड़ितों के पक्ष में बातें रखकर गहलोत सरकार को घेरने का काम किया है। सचिन पायलट की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ को देखकर गहलोत के हाथ पांव फूल गए। उन्होने अपने मंत्रियों को तुरंत प्रदेश के दौरे पर रवाना कर जन समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। पायलट को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि गहलोत के सामने कांग्रेस आलाकमान बेबस हो रहा है। सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी चाहे पायलट के धैर्य की कितनी भी तारीफ करें। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पायलट जान चुके हैं कि फिलहाल गांधी परिवार उन्हें सिर्फ दिलासा के अलावा और कुछ नहीं दे सकता हैं। मुख्यमंत्री गहलोत पायलट को बार-बार कांग्रेस से बगावत करने वाले नेता के तौर पर कठघरे में खड़ा करते रहते हैं। मगर गहलोत द्वारा स्वयं ही पार्टी आलाकमान के निर्देशों को नहीं मानकर खुलेआम बगावत करने की घटना को गहलोत मात्र एक छोटी सी भूल बताकर उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। गहलोत समर्थक विधायकों द्वारा 25 सितंबर 2022 को जयपुर में कांग्रेस पर्यवेक्षक मलिकार्जुन खरगे व अजय माकन की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक दल के समानांतर कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के घर पर अलग से विधायकों की मीटिंग आयोजित कर विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने की घटना को गहलोत सिर्फ माफी मांग कर समाप्त कर देना चाहते हैं। उस घटना के बाद गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांग कर अपने को पाक साफ कर लिया था। जबकि सचिन पायलट को गहलोत अभी तक भी गुनाहगार मानते आ रहे हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान से इस बात को लेकर भी गहरी नाराजगी है कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने समानांतर मीटिंग बुलाने के दोषी कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी व पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस अनुशासन समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए हुए करीबन साढ़े तीन माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। इतना ही नहीं उस घटना के दोषी तीनों ही नेता पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। पायलट कई बार कारण बताओ नोटिस देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर चुके हैं। उसके उपरांत भी अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है।

इससे पायलट को लगता है कि मुख्यमंत्री गहलोत के दबाव में कांग्रेस आलाकमान इन तीनों नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही को टाल रहा है। जबकि सचिन पायलट ने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली के खिलाफ बगावत की थी तब उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री के पद से तथा उनके समर्थक तीन मंत्रियों महाराजा विश्वेंद्र सिंह रमेश मीणा मुरारी लाल मीणा को तत्काल पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट की नजरों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पायलट समर्थक सैनिक कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का कहना है कि 2013 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। जिसमें कांग्रेस 200 में से महज 21 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी थी। जबकि 2018 में सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। तब कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते 100 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। ऐसे में उस वक्त 200 में से 21 सीट जीतने वाले को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जबकि 200 में से 100 सीट जीतने वाले को उप मुख्यमंत्री ही बनाया गया था। पायलट के साथ उस समय किया गया भेदभाव अभी तक जारी है। अब तो पायलट समर्थक भी मानने लगे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत ही अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगें। ऐसे में पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें राजनीतिक रूप से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सचिन पायलट ने अपनी रणनीति बदल ली है।

हालांकि सचिन पायलट के पास सत्ता नहीं रहने के कारण विधायकों की संख्या कम है। विधायकों के संख्या बल पर ही मुख्यमंत्री गहलोत आलाकमान से अपनी हर बात मनवा लेते हैं। ऐसे में सचिन पायलट का पूरा फोकस युवा वर्ग पर हो गया है। सचिन पायलट गहलोत शासन में सरकारी परीक्षाओं के लगातार पेपर आउट होने पर खुलकर विरोध जता रहे हैं। पायलट ने तो यहां तक कह दिया की पेपर नकल करवाने वाले गिरोह के सरगनाओं को नहीं पकड़ा जा रहा है।

राजस्थान में पिछले 4 साल में 14 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। पायलट का मानना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पेपर तिजोरी में बंद रहते हैं तो फिर बंद तिजोरी से पेपर कौन से जादू के बल पर आउट हो रहे हैं। सचिन पायलट द्वारा यह एक तरह से सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है।

पायलट के बयानों को युवाओं में भारी समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते पायलट जहां भी जाते हैं बड़ी संख्या में नौजवान उनका समर्थन करने पहुंच रहे हैं। हाल ही में पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। पायलट ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वसुंधरा राज्य के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी।

विचार मंथन

शेयर बाजार को भी समझ नहीं आया आम बजट

(लेखक/ सनत कुमार जैन)

-आयकर छूट के नाम पर वाहवाही

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आखिरी बजट प्रस्तुत कर दिया है। जैसा माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए यह लोकलुभावन बजट होगा। मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए वित्त मंत्री ने आयकर की नई श्रेणी बनाई है इसमें 3 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह से कर मुक्त किया गया है। 3 से 6 लाख रुपए की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स 6 से 9 लाख की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स 9 से 12 लाख की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स और 12 से 15 लाख की आय पर 20 फ़ीसदी टैक्स की घोषणा बजट में की है। सरकार ने जो दावा किया है इससे नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के करदाताओं को 15 हजार से लेकर 150000 रूपये तक का लाभ मिलेगा। जैसे ही संसद में इसकी घोषणा हुई उसके तुरंत बाद शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगा दी। शेयर बाजार में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1200 अंक चढ़कर कारोबार करने लगा लेकिन जैसे ही बजट में यह खुलासा हुआ कि आयकर का जो नया स्लैब घोषित किया गया है। उसमें धारा 80 की छूट नहीं मिलेगी। आयकर की जो पुरानी स्लैब की दरें हैं। उन्हीं पर धारा 80 की छूट मिलेगी। उसके बाद शेयर बाजार में गिरावट शुरु हो गई।

मध्यमवर्ग को 1 लाख 50000 तक की आयकर पर धारा 80जी की जो छूट मिलती थी। वह नए सिलेब में खत्म कर दी गई हैं। मध्यमवर्ग जो जीवन बीमा निगम पीपीएफ ईपीएफ बचत खाते यूनिटनेशनल पेंशन स्कीम और होम लोन इत्यादि में जो ब्याज की छूट मिलती थी। अब आयकर की नई स्कीम में छूट नहीं मिलेगी। इसके तुरंत बाद शेयर बाजार ने गोता लगाना शुरू कर दिया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो 1200 अंक की ऊंचाई के साथ 60773.44 अंक पर कारोबार कर रहा था। वह मंगलवार की तुलना में मात्र 162.43 अंक चढ़कर 59712.33 पर बंद हुआ। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट को लोकलुभावन बजट बनाने का हर संभव प्रयास किया। मीडिया ने शुरुआती दौर में उसे लोकलुभावन बजट मानकर छूट के फायदे गिनाए। लेकिन सही मायने में इस बजट का लाभ ना तो मध्यमवर्ग को मिल रहा है ना ही गरीबों को मिल रहा है।

बजट में खिलौने इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी टेलीविजन चेनल पर कस्टम और आयात शुल्क को कम करने की घोषणा की गई। आयकर की जो 2 नई श्रेणी बनाई गई हैं उसमें भी आंकड़ों की हेराफेरी जब लोगों की समझ आई। उसके बाद से ही बजट को लेकर लोगों में निराशा देखने को मिलने लगी। प्रति व्यक्ति आय सरकार ने बढ़ी हुई बताई है। लेकिन महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा आय की तुलना में महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लोग हैरान और परेशान हैं। कुल मिलाकर बजट में जिस तरह की आशा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग कर रहा था। वह देखने को नहीं मिला इसका असर तुरंत ही शेयर बाजार पर भी

दिखने लगा। बजट भाषण के पश्चात जब इसका विश्लेषण होना शुरू हुआ शुरुआती दौर में शेयर बाजार में बजट की जो चमक बनी थी वह धीरे-धीरे धूमिल पड़ गई।

बजट में बेरोजगारी महंगाई किसानों की मांग मध्यम आय वर्ग के लिए आयकर में कटौती कर्ज और ब्याज जैसी समस्याओं का ध्यान बजट में नहीं रखा गया। पुरानी पेंशन योजना और बेरोजगारी पर बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला। बजट प्रस्तुत होने के साथ ही शेयर बाजार पहले झूमा था बाद में तेजी के साथ गिरता चला गया। अडानी समूह को लेकर हिंडन बर्ग की जो रिपोर्ट आई है। उसने सरकार और वित्तीय संस्थाओं की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारत की जीडीपी में शेयर बाजार की भी बड़ी हिस्सेदारी है। शेयर बाजार की विश्वसनीयता पर यदि प्रश्न चिन्ह लगेंगे तो इसका असर भी सरकार के बजट और विदेशी निवेश पर भविष्य में पड़ना तय माना जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है। उससे बजट में उनके सामने बड़ा धर्मसंकट देखने को मिल रहा है। चुनावी वर्ष होने के बाद भी सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव इतना ज्यादा है कि आयकर की 2 श्रेणियां बनाने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दे पाई हैं।

महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर भी बजट में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो मध्यम और निम्न वर्ग को राहत पहुंचाने वाला हो। इसे लोकलुभावन बजट भी नहीं माना जा सकता हे। जो 9 राज्यों और 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने वाला साबित हो।

सीतारमण के बजट में नौकरीपेश हर वर्ग को थोड़ी राहत नई टैक्स प्रणाली लागू

नई दिल्ली ।

मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट 2023-24 पेश कर दिया। बजट में नए टैक्स रेजीम में 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर पहले जहां 23400 रुपये का टैक्स देना होता था वहीं अब इस कमाई पर 15600 रुपये का टैक्स देना होगा। यानी अब इस पर 7800 रुपये का फायदा होगा। हालांकि इस आय तक शामिल टैक्‍ सपेयर्स को अब रिबेट मिलेगी जिससे उनकी देनदारी शून्य होगी। वहीं नौकरीपेशा व्‍यक्ति अगर सालाना 8 लाख रुपये कमाता है तब पहले नौकरीपेशा को इस कमाई पर 46800 रुपये इनकम टैक्स के रूप में चुकाने पड़ते थे। टैक्स की दरें घटाने के बाद अब करदाताओं को 8 लाख तक की कमाई पर 36400 रुपये का टैक्स चुकाना होगा। यानी आपको सीधे तौर पर 10400 रुपये की टैक्स बचत होगी। 9 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को अभी तक जहां 62400 रुपये का इनकम टैक्‍ स चुकाना होता था वहीं अब नई दरें लागू होने के बाद यह देनदारी घटकर 46800 करोड़ रुपये होगी। यानी 9 लाख की सालाना कमाई करने वाला व्‍यक्ति अब हर साल टैक्स पर 15600 रुपये बचा सकेगा। इस तरह 10 लाख रुपये सालाना कमाने वाला नए टैक्स रेजीम में पहले इस पर 78 हजार रुपये का इनकम टैक्स भरता था। टैक्स की दरें घटाने के बाद यह देनदारी गिरकर 57200 रुपये हो गई है। यानी अब टैक्‍ सपेयर्स को 10 लाख तक की कमाई पर सीधे तौर पर 20800 रुपये का टैक्‍ स पर फायदा होगा। मोटी कमाई वाले कर्मचारियों को टैक्‍ स में छूट भी बड़ी दी गई है। नए टैक्स रेजीम के तहत पहले जहां 15 लाख रुपये तक की कमाई पर 2.37 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा वहीं अब नई दरें लगाने के बाद यह राशि घटकर 1.40 लाख रुपये हो गया है। यानी आपको इस कमाई पर सीधे तौर पर 106600 रुपये टैक्स बचेगा।

क्या है नए टैक्स रेजीम के टैक्स स्लैब

नई टैक्स प्रणाली में पहला स्लैब 3-6 लाख रुपये का है जिस पर 5 फीसदी टैक्स है लेकिन रिबेट लागू होने के कारण यहां प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद 6-9 लाख रुपये की टैक्स स्लैब जिसमें 10 फीसदी कर देना होता है। ध्यान रहे कि 7 लाख तक की आय रिबेट में आती है तब वहां भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 9-12 लाख का स्लैब जिस पर 15 फीसदी टैक्स 12-15 लाख के स्लैब पर 20 और 15 लाख रुपये से अधिक के स्लैब पर 30 फीसदी टैक्स है।

पुरानी रिजीम के टैक्स स्लैब

पुरानी रिजीम में 2.5-5 लाख पर 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी का टैक्स है। 5 लाख से अधिक से लेकर 7.5 लाख तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स है। 7.5 से ऊपर और 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स लिया जाता है। इसके बाद 10 लाख से अधिक से 15 लाख रुपये तक 30 फीसदी टैक्स है। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक केवल 15 फीसदी टैक्स है जबकि पुरानी में 7.5 लाख के बाद से ही 20 फीसदी टैक्स शुरू होता है।

7 लाख से अधिक की आय पर कहां ज्यादा फायदा?

नई टैक्स प्रणाली में बदलाव के बाद से 10 लाख रुपये के अंदर की आय वाले लोगों के लिए ये और लुभावनी हो गई है। क्योंकि 9 लाख रुपये तक की आय पर अपडेटेड न्यू टैक्स रिजीम में केवल 10 फीसदी ही टैक्स है। दूसरी ओर पुरानी टैक्स व्यवस्था में करदाता को इतने ही वेतन पर 20 फीसदी टैक्स भरना होता है। हालांकि पुरानी यानी कि 2020 से पहले कि टैक्स व्यवस्था में आपको कई निवेश पर छूट भी मिलती हैं।

टाटा मोटर्स की कुल बिक्री जनवरी में 6.4 प्रतिशत बढ़कर 81069 इकाई पर

मुंबई । टाटा मोटर्स की कुल बिक्री जनवरी 2023 में 6.4 प्रतिशत बढ़कर 81069 इकाई हो गई। टाटा ने जनवरी 2022 में कुल 76210 इकाइयां बेची थीं। टाटा मोटर्स ने कहा कि अवधि के दौरान घरेलू बाजार में उसकी कुल बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 79681 इकाई पर पहुंच गयी। एक साल पहले इसी महीने में उसने 72485 इकाइयां बेची थीं। कंपनी ने कहा कि आलोच्य महीने के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उसके यात्री वाहनों की घरेलू स्तर पर बिक्री भी 18 प्रतिशत बढ़कर 48289 इकाई रही। यह पिछले साल इसी महीने में 40942 इकाई थी। हालांकि पिछले महीने घरेलू बाजार में इसकी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री सात प्रतिशत घटकर 32780 इकाई रह गई। जनवरी 2022 में यह संख्या 35268 इकाई थी।

सोने और चांदी में तेजी

नई दिल्ली । घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी में तेजी आई है। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1090 रुपये की बढ़त के साथ ही 57942 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गयीं। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56852 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी की कीमत भी 1947 रुपये के उछाल के साथ 69897 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई जबकि गत कारोबारी सत्र में चांदी 67950 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 1090 रुपये की तेजी के साथ 57942 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी। वहीं विदेशी बाजारों में सोना उछाल के साथ ही 1923 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी गिरावट के साथ 23.27 डॉलर प्रति औंस पर थी। बाजार जानकारों के अनुसार कॉमेक्स में सोने की हाजिर कीमत अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 1923 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। डॉलर के कमजोर रहने तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर की धीमी वृद्धि दर से सोने की कीमतें लगातार तीसरे महीने बढ़ी हैं।

सोने की ईजीआर में अदला-बदली पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं: वित्त मंत्री

नयी दिल्ली, सोने की धातु को 'इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीद' (ईजीआर) में बदलने या ईजीआर को सोने में बदलने पर कोई भी पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में अपने बजट भाषण में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, ''स्वर्ण धातु को ईजीआर में बदलने या ईजीआर को सोने में बदलने की प्रक्रिया को हस्तांतरण नहीं मानने और उस पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।''सरकार की इस घोषणा से सोने के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप ईजीआर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ईजीआर शेयर बाजार पर कारोबार की जाने वाली डिपॉजिटरी स्वर्ण प्राप्तियां हैं। इस रूप में निवेशक सोने के इलेक्ट्रॉनिक रूप की खरीदारी करते हैं और उन्हें सोना धातु के स्थान पर स्वर्ण प्राप्तियां दी जाती हैं।

ऑटो सेक्टर को मिली सौगात स्क्रैप पॉलिसी पर दिया गया जोर

नई दिल्ली ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने केंद्रीय बजट 2023 के भाषण में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ घोषणाएं कीं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर जोर दिया गया है। इस बार का बजट ऑटो सेक्टर के लिए उतना खास नहीं रहा है। साल 2023 के बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि साल 2022 के बजट के अनुसार सभी पुरानी गाड़ियों और एंबुलेंस को स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने प्रदूषण करने वाले वाहनों को स्क्रैप करना हमारी अर्थव्यवस्था को हरित बनाने में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा निर्माला सीतारमण ने कहा कि आने वाले समय में ईवी की कीमत कम हो जाएगी।

पिछले साल बजट-2022 में हुई थी ये घोषणाएं

पिछले साल के बजट में ऑटो सेक्टर को उतनी खास जगह नहीं मिली थी जितना इस सेक्टर को उम्मीद थी। पिछले साल के बजट में ईवी को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लागू करने की बात की गई थी। साल-2022 में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लागू की जाएगी जिससे बड़े पैमाने पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटरऑपरेबिलिटी मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और अभिनव मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो ईवी में दक्षता बढ़ाएगा।

आम बजट 2023: बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का रखा गया ध्यान : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच अब तक के सर्वाधिक परिव्यय 2013-14 में किए गए परिव्यय का नौ गुना की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय था जो 2013-14 में किए गए परिव्यय का नौ गुना था। पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। राज्यों को प्रोत्साहन देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को दिया जाने वाला 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक साल और जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग का राज्य समर्थन मिशन तीन साल तक जारी रहेगा। अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी।

इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज़ मिलेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.ह्व की शुरूआत की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5त्न का ब्याज़ मिलेगा।

जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

अडानी ग्रुप के शेयरों में हाहाकार! 28 प्रतिशत तक टूटे

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बजट 2023 के दिन हरे निशान पर बंद हुआ है। लेकिन अडानी ग्रुप के लिए बुधवार का दिन शेयर बाजार में अच्छा नहीं रहा। अडानी ग्रुप के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त गिरावट देखी गई है। जो अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था उसमें आज 25 फीसदी से अधिक की गिरावट आई। अडानी के शेयरों में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 0.27 फीसदी या 162.43 रुपये बढ़कर 59712.33 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह अधिकतम 60773.44 अंक तक और न्यूनतम 58816.84 अंक तक गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकाकं निफ्टी बजट के दिन लाल निशान पर बंद हुआ है। एनएसई निफ्टी 0.26 फीसदी या 45.85 अंक गिरकर 17616.30 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह अधिकतम 17972.20 अंक तक और न्यूनतम 17353.40 अंक तक गया। बाजार बंद होते समय निफ्टी के 50 शेयरों में से 23 शेयर हरे निशान पर और 27 शेयर लाल निशान पर थे।

अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर बुधवार को 28.45 फीसदी या 846.30 रुपये के नुकसान के साथ 2128.70 रुपये पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान यह न्यूनतम 1942 रुपये तक गया था। अडानी पोर्ट्स के शेयर में भी जबरदस्त गिरावट आई। यह शेयर 19.69 फीसदी या 120.65 रुपये गिरकर 492.15 रुपये पर बंद हुआ।

अडानी पावर के शेयर में भी बुधवार को लोअर सर्किट लगा। यह शेयर 4.98 फीसदी या 11.15 रुपये गिरकर 212.75 रुपये पर बंद हुआ। अडानी ट्रांसमिशन का शेयर बुधवार को 2.46 फीसदी या 43.70 रुपये गिरकर 1730.25 रुपये पर बंद हुआ। वहीं अडानी ग्रीन का शेयर 5.78 फीसदी या 70.70 रुपये टूटकर 1153.35 रुपये पर बंद हुआ।

बजट के बाद रुपये में गिरावट

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया नीच आया है। सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किये जाने के बाद अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये का शुरुआती लाभ समाप्त हो गया और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया मुद्रा दो पैसे टूटकर 81.90 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुई। यह गिरावट निवेशकों के कारोबार से दूर रहने के कारण आई हैं। आज सुबह अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.76 पर खुला पर कारोबार के अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव से दो पैसे टूटकर 81.90 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रुपया 81.68 के दिन के उच्चस्तर और 82.03 के निम्न स्तर पर पहुंचा। वहीं गत कारोबारी सत्र में रुपया 36 पैसे की गिरावट के साथ ही 81.88 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। वहीं इसी बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14 फीसदी नीचे आकर 101.95 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.26 फीसदी फिसलकर 85.24 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

बजट का बाजार पर मिला-जुला असर

सेंसेक्स 158.18 अंक उछला निफ्टी 45.85 अंक गिरा

मुंबई ।

मुम्बई शेयर बाजार में बुधवार को 2023-24 का बजट पेश होने के बीच ही उतार-चढ़ाव जारी रहा। शुरुआत में बाजार 1223.54 अंक तक उछला पर बाद में बिकवाली हावी होने से दोनों ही इसमें गिरावट आने लगी। दिन भर के कारोबार के बाद बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 158.18 अंक करीब 0.27 फीसदी की बढ़त के साथ ही 59708.08 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी में 45.85 अंक यानी 0.26 फीसदी की गिरावट आई। इसी के साथ ही निफ्टी 17616.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में आईटीसी टाटा स्टील आईसीआईसीआई बैंक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर ऊपर आये जबकि बजाज फिनसर्व भारतीय स्टेट बैंक इंडसइंड बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में गिरावट आई। बाजार जानकारों के अनुसार बजट में खपत और पूंजीगत व्यय पर खासा जोर दिया गया है। इससे बाजार को अच्छी उम्मीदें मिली पर अडाणी और फेडरल रिजर्व के कारण निवेशकों की निकासी से बाजार नीचे आने लगा। इसके अलावा सरकार की ओर से नई कर प्रणाली को बढ़ावा देने से जीवन बीमा कंपनियों के कम आकर्षक रह जाने की आशंका से भी मुनाफावसूली बढ़ी।बजट में हालांक कोई नकारात्मक घोषणा न होने से बाजार को बल मिला। अब निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व की मौद्रिक घोषणा पर टिकेगी। वहीं दुनिया भर के बाजारों में कुल

मिलाकर सकारात्मक रुख रहने से भी निवेशकों में उत्साह आया। वहीं एशियाई और अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी जापान का निक्की चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में भी उछाल रहा। वहीं अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.05 फीसदी की गिरावट के साथ 85.42 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

बजट सकारात्मक होने के साथ ही दूर की सोच वाला : निजी स्वास्थ्य क्षेत्र

हैदराबाद,

संसद में मंगलवार को पेश आम बजट में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की निजी कंपनियों के प्रमुखों का ऐसा मानना है। उनका कहना है कि यह बजट सकारात्मक होने के साथ ही दूरदर्शी सोच वाला भी है।अपोलो समूह-अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. के हरि प्रसाद ने एक बयान में कहा कि भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र देश की प्रगति का निर्धारण करने वाला अहम सामाजिक-आर्थिक पहलू होगा।प्रसाद ने कहा, ''इस बजट में स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दिया गया है...हालांकि, पूरी स्पष्टता तो पूरा बजट दस्तावेज सामने आने पर ही मिलेगी लेकिन आरंभिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह बजट सकारात्मक होने के साथ-साथ दूर की सोच रखने वाला है।''

उन्होंने कहा कि पुरानी एम्बुलेंस को नई से बदलने पर, अस्पताल पहुंचने से पहले की आपात देखभाल का स्तर सुधरेगा और इससे जिंदगियां बचाने में मदद मिलेगी।

प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी व्यय बीते आठ वर्षों में दोगुना हो गया है और इसमें अभी और इजाफा होगा।

कामिनेनी हॉस्पिटल्स में प्रबंध निदेशक कामिनेनी शशिधर ने कहा कि व्यापक स्तर पर सख्त परिदृश्य को देखते हुए इसे एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की पहल स्वागतयोग्य है।

ग्रीन फ्यूल एनर्जी पर जोर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में गिरावट की उम्मीद

नई दिल्ली ।

बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 को पेश किया है। बजट के बाद क्या गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएगी या फिर सस्ती होंगी इसके बारे में आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बजट 2023 में वित्त मंत्री ने कहा कि देश में इनदिनों ग्रीन फ्यूल एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। देश में हो रहे पॉल्यूशन को कम करने के लिए बैटरी स्वाइपिंग नीति के तहत उन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा जिनकी आयु समाप्त हो गई है। इसके अलावा इस बजट में यह भी बताया गया कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में ईवी सस्ती होगी। इसके बाद अगर आप नई ईवी खरीदना चाहते हैं तब आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं।

जैसा कि आपको पहले ही पता है कि 1 अप्रैल 2023 से सरकार बीएस 6 का दूसरा चरण लागू करने जा रही है इसके बाद ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों में नए नार्म्स के अनुसार बदलाव कर रही हैं। नए चरण के लागू होते ही कयास लगाया जा रहा है कि भारत में गाड़ियों की कीमतों में इसका अच्छा-खासा असर देखने को मिल सकता है।

अगर आप विदेशों से लग्जरी कार या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट कराने का प्लान बना रहे हैं तब आप को इसकी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंपोर्टेड लग्जरी कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो कस्टम ड्यूटी थी उस बढ़ाकर 70 फीसद कर दिया गया है। इस बजट के बाद गाड़ी खरीदना महंगा हो सकता है।

टॉप 10 में गौतम अदानी की फिर हुई वापसी तीन दिन की गिरावट के बाद नेटवर्थ में तेजी

- हिडेन बर्ग की सूनामी से उबरे अदानी

नई दिल्ली ।

तीन दिन की गिरावट के बाद नेटवर्थ में तेजी आने से गौतम अदानी की टॉप 10 में फिर हुई वापसी हो गई। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडेन बर्ग रिसर्च की सूनामी से अब अदानी ग्रुप उबरने लगा है। तीन दिन की भारी गिरावट के बाद मंगलवार को ग्रुप के अधिकांश शेयरों में तेजी रही। इससे ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की नेटवर्थ में भी तेजी आई है और वह एक बार फिर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक मंगलवार को अदानी की नेटवर्थ में 9.96 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और अब यह 84.5 अरब डॉलर पहुंच गई है। हिडेन बर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। इस अमेरिकी फर्म ने पिछले हफ्ते बुधवार को एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अदानी ग्रुप दशकों से खुल्लम-खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। इससे तीन दिन अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और उसका मार्केट कैप 75 अरब डॉलर घट गया। हालांकि अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा है कि यह एफपीओ से पहले उसे बदनाम करने की साजिश है।

अदानी ग्रुप की अधिकांश कंपनियों में मंगलवार को तेजी रही। ग्रुप की 10 कंपनियों में से सात तेजी के साथ बंद हुईं जबकि तीन कंपनियों में लोअर सर्किट लगा। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 3.35 फीसदी तेजी आई। इसी तरह अदानी ट्रांसमिशन में 3.73 फीसदी अदानी ग्रीन एनर्जी में 3.06 फीसदी अदानी पोर्ट्स में 2.67 फीसदी अंबूजा सीमेंट्स में 3.50 फीसदी एसीसी लिमिटेड में 3.39 फीसदी और एनडीटीवी में 1.35 फीसदी तेजी आई। दूसरी ओर अदानी टोटल गैस में 10 फीसदी अदानी विल्मर और अदानी पावर में पांच फीसदी गिरावट रही।

अदानी ने पिछले साल 44 अरब डॉलर की कमाई की और वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अमीर थे लेकिन इस साल वह 36 अरब डॉलर गंवा चुके हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले अरबपति हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टेस्ट क्रिकेट के बिना सफल करियर नहीं बना सकते : वार्नर

सिडनी । हाल के दिनों में जिस प्रकार टी20 क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी है। उससे टेस्ट क्रिकेट के साथ ही एकदिवसीय मैचों के प्रति भी लोगों का रुझान घट है। ऐसे में युवा क्रिकेटर सीमित ओवरों के क्रिकेट की ओर जा रहे हैं जिससे दिग्गजों को लाल गेंद के क्रिकेट के भविष्य पर संकट नजर आ रहा है। अब यही आशंका ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी जतायी है। वार्नर के अनुसार उन्हें टेस्ट क्रिकेट का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है क्योंकि युवा क्रिकेटर खेल के सबसे लंबे प्रारूप पर सफेद गेंद वाले क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस सलामी बल्लेबाज ने युवाओं से कहा कि क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट खेले बिना एक लंबा और सफल करियर नहीं बना सकता इसलिए उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने पर विचार करना चाहिये। वार्नर ने सिडनी थंडर के अपने एक साथी क्रिकेटर ओलिवर डेविस का उदाहरण देते हुए बताया कि जब प्रारूपों के बीच चयन करने की बात आती है तो आने वाले क्रिकेटर सीमित ओवरों को ही प्राथमिकता देत हैं। वार्नर ने कहा कि उन्होंने बिग बैश लीग में खेलने के दौरान डेविस सहित अपने युवा साथियों को टेस्ट क्रिकेट की अहमियत समझाने का प्रयास किया पर असफल रहा।

विश्व शतरंज रैंकिंग: रूस को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत

नई दिल्ली विश्व शतरंज संघ द्वारा 1 फरबरी को जारी ताजा विश्व शतरंज रैंकिंग में टीम रैंकिंग में महिला वर्ग में भारत नें 1 अंक से रूस को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है । शतरंज इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत नें रूस को पीछे छोड़ा है । टीम रैंकिंग देश के 10 शीर्ष खिलाड़ियों की औसत रेटिंग के आधार पर तय होती है । 2470 अंको के साथ चीन पहले तो भारत 2413 दूसरे और रूस 2412 के साथ तीसरे स्थान पर है । पुरुष वर्ग की टीम रैंकिंग में यूएसए की टीम 2728 अंको के साथ पहले, रूस 2702 अंको के साथ दूसरे तो भारत अब 2690 अंको के साथ तीसरे नंबर की टीम बनी हुई है । पुरुष वर्ग की व्यक्तिगत रैंकिंग में विश्व शतरंज चैम्पियन मेगनस कार्लसन 2852 अंको के साथ पहले स्थान पर बने हुए है ,जुलाई 2011 के बाद से कार्लसन लगातार 11 साल 7 माह से विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए है । भारत के विश्वनाथन आनंद नें टॉप 10 में अपना स्थान बनाए रखा है ,52 वर्षीय आनंद 2754 अंको के साथ नौवे स्थान पर है अन्य भारतीय खिलाड़ियों में विदित गुजराती (2730)19वे ,डी गुकेश(2718) 29वे,पेंटाला हरीकृष्णा (2705) 36वे ,अर्जुन एरिगासी (2701) 38वे और प्रज्ञानन्दा (2690) 46वे स्थान पर है । महिला व्यक्तिगत विश्व रैंकिंग में चीन की हाउ ईफ़ान 2638 अंको के साथ पहले ,रूस की अलेकसान्द्रा गोरयाचकिना 2576 अंको के साथ दूसरे तो भारत की कोनेरु हम्पी 2572 अंको के साथ तीसरे स्थान पर है । भारत की हरिका द्रोणावल्ली 2507 अंको के साथ 12वे तो आर वैशाली 2433 अंको के साथ 31वे स्थान पर है ।

बजट में खेलों का भी रखा गया ध्यान

नई दिल्ली ।

केन्द्रीय बजट में खेल मंत्रालय का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस साल होने वाले एशियाई खेलों और 2024 पेरिस ओलंपिक को देखते हुए 700 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान रखा गया है। बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3397.32 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है यह पिछले साल के मुकाबले 723.97 करोड़ रुपये अधिक है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के संशोधित बजट से अधिक है। उस समय खेल मंत्रालय को 2673.35 करोड़ रुपये मिले थे। पिछले साल हालांकि वास्तविक आवंटन 3062.60 करोड़ रुपये था। देश में प्रतिभाओं को सामने लाने वाले खेल मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम 'खेलो इंडिया' के लिए भी राशि बढ़ायी गयी है। इसे 1045 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 606 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इस प्रकार आवंटन में 439 करोड़ रुपये बढ़ाये गये हैं। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए इस बजट आवंटन में 36.09 करोड़ रुपये बढ़ाये गये हैं। पिछले वर्ष के संशोधित व्यय 749.43 करोड़ रुपये के मुकाबले साल 2023-24 के लिए उनका आवंटन 785.52 करोड़ रुपये है। खिलाड़ियों के खेल विज्ञान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने के लिए इस साल के बजट में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के लिए भी 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को पिछले वर्ष के संशोधित बजट 280 करोड़ रुपये के मुकाबले 45 करोड़ रुपये अधिक मिलने के साथ ही अब कुल 325 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) से संबद्ध राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीएलटी) को अब सीधे ही राशि मिलेगी। बजट में नाडा को 21.73 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया करायी गयी है जबकि डोप परीक्षण कराने वाले एनडीटीएल को 19.50 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

ब्रिटेन की भीषण त्रासदी के 34 साल बाद पुलिस ने माफी मांगी

(एजेंसी)।

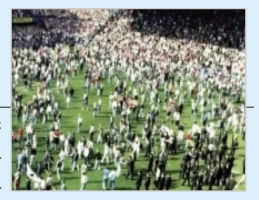

ब्रिटेन के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने माना कि पुलिस की विफलता 1989 की हिल्सबोरो दुर्घटना का मुख्य कारण थी, जब लिवरपूल एफसी के 97 प्रशंसक मारे गए थे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एक ऐतिहासिक संयुक्त बयान में कॉलेज ऑफ पुलिसिंग और नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल (एनपीसीसी) के नेताओं ने हिल्सबोरो के परिवारों से माफी मांगी।हिल्सबोरो परिवार रिपोर्ट की प्रस्तावना में, मुख्य कांस्टेबल एंडी मार्श, पुलिसिंग कॉलेज के सीईओ और एनपीसीसी के अध्यक्ष मार्टिन हेविट ने कहा, 97 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गैरकानूनी रूप से मार दिया गया था। पुलिस की विफलता इस त्रासदी का मुख्य कारण थी और पुलिस की विफलता तब से परिवार के सदस्यों के जीवन को कलंकित करती रही है।1989 में लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच एफए कप सेमीफाइनल में 97 दर्शक मारे गए और लगभग 800 घायल हो गए। शेफील्ड के हिल्सबोरो स्टेडियम में खेल कुछ ही मिनटों के बाद रद्द कर दिया गया। त्रासदी के बाद से, लिवरपूल एफसी द्वारा समर्थित प्रशंसकों ने न्याय के लिए संघर्ष किया है।मार्श ने कहा, पुलिस की गैर जवाबदेही के चलते ऐसा हुआ। पुलिस की विफलता त्रासदी का मुख्य कारण थी और तब से परिवार के सदस्यों के जीवन को कलंकित करती रही है।जब नेतृत्व की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तो शोक संतप्त लोगों के साथ अक्सर असंवेदनशील व्यवहार किया जाता था और प्रतिक्रिया में समन्वय और निरीक्षण की कमी होती थी।

मैं भी मीराबाई बनना चाहती हूँ...

कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद पहले खेलो इंडिया के लिए तैयार हैं महाराष्ट्र की 14 साल की वेटलिफ्टर आकांक्षा

इन्दौर ।

आकांक्षा व्यवहारे की उम्र सिर्फ 14 साल है लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े हैं। अपने वेट कैटेगरी में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद टॉप डेवलपमेंट लिस्ट में नाम दर्ज करा चुकीं आकांक्षा पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकीं आकांक्षा इस प्लेटफार्म का पहली बार उपयोग करने को लेकर काफी उत्साहित और रोमांचित हैं।

भारत की ओलंपिक पदकधारी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की राह पर चलने की इच्छा रखने वाली मनमाड़ में अभ्यास करती हैं। आकांक्षा अपने देश के लिए पदक जीतना चाहती हैं। आकांक्षा ने कहा- मैं मीराबाई चानू की तरह बनना चाहती हूं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने कई सारे त्याग किए हैं और इसी कारण वह आज इस मुकाम पर हैं। खेलो इंडिया के लिए साई रिजनल सेंटर औरंगाबाद में प्रैक्टिस कर रहीं आकांक्षा ने बताया कि अपनी प्रेरणास्रोत मीराबाई से वह एक बार मिली हैं और उन्हें काफी अच्छा लगा था। आकांक्षा ने कहा- इंटरनेशनल के लिए जाते वक्त मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा था कि तुम अच्छा कर रही है। इसी तरह मेहनत करती रहो। सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान लगाओ। आकांक्षा ने छोटी सी उमर में ढेर सारी सफलता हासिल की है। मार्च 2022 में आकांक्षा ने ओडिशा नेशनल्स में हिस्सा लिया था और इसमें उन्होंने 40 किग्रा कैटेगरी में 6 नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे और गोल्ड जीता था। फिर अगस्त 2022 में आकांक्षा ने पटियाला में आयोजित नेशनल्स में हिस्सा लिया था। उसमें 40 किग्रा कैटेगरी में उन्हें गोल्ड मिला था। 2022 में ही आकांक्षा ने मेक्सिको में आयोजित इंटरनेशनल इवेंट में ओवरआल सिल्वर जीता था। स्नैच में मेरा गोल्ड था। वहां मैंने स्नैच में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। फिर मैंने एशियन यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल जीता था। उस समय मैंने क्लीन एंड जर्क में 70 किग्रा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। मौजूदा समय में स्नैच

में 60 किग्रा का तथा क्लीन एंड जर्क में 71 किग्रा का नेशनल रिकॉर्ड है जो मैंने मोदीनगर में आयोजित खेलो इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप में बनाया था। साथ ही 40 किग्रा कैटेगरी में 131 किग्रा का नेशनल रिकॉर्ड है। बीते साल टाप्स में आने वाली आकांक्षा मानती हैं कि इस सूची में आने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।

संक्षिप्त समाचार

आईसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्यकुमार शीर्ष पर बरकरार

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ताजा टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव शीर्ष पर बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन से सूर्यकुमार के कुल मिलाकर 910 अंक है और बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में वह नंबर एक पर पहुंच गये हैं। वर्तमान रेटिंग अंक का अर्थ है कि सूर्यकुमार पुरुषों के टी20आई बल्लेबाजों के लिए सर्वकालिक उच्चतम रेटिंग रखने की दौड़ में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मालन के करीब होंगे। मालन ने साल 2020 में केप टाउन में 915 अंकों की रेटिंग हासिल की वहीं सूर्यकुमार अब टी20आई बल्लेबाजों के लिए अब तक की दूसरी सबसे बड़ी रेटिंग रखते हैं। सूर्या के साथी वाशिंगटन सुंदर को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छे प्रदर्शन का लाभ मिला है और वह अब 104वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के फिन एलन आठ स्थान ऊपर आकर 19वें स्थान पर पहुंच गये हैं जबकि डेरिल मिशेल 9 स्थान की छलांग लगाकर 29वें स्थान पर पहुंच गये हैं। दूसरी ओर गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल छह स्थान ऊपर आकर 34वें और कुलदीप यादव 54 स्थान के लाभ के साथ ही 81वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शीर्ष दस में न्यूजीलैंड के एक स्पिनर मिचेल सेंटनर शामिल हैं।

ख्वाजा के बिना ही भारत पहुंची ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

नई दिल्ली । भारतीय टीम के साथ नौ फरवरी से होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भारत पहुंच गयी है पर वीजा नहीं मिलने के कारण बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा नहीं आये हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देखते हुए यह सीरीज दोनो ही टीमों के लिए अहम है। ऐसे में उनका लक्ष्य जीत दर्ज करना रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ बल्लेबाज ख्वाजा नहीं आये हैं क्योंकि उनको वीजा नहीं मिला। ख्वाजा ने उड़ान नहीं पकड़ पाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने कहा कि ख्वाजा का वीजा क्लियर नहीं हुआ था इसलिए वह भारत नहीं जा पाये हैंहै। वह अब भारत दौरे के लिए गुरुवार को उड़ान भरेंगे। इससे साफ है कि यह बल्लेबाज गुरुवार को होने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीम के अभ्यास सत्र में नहीं खेल पायेगा। पाकिस्तानी मूल के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का जन्म इस्लामाबाद में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से अभी तक 56 टेस्ट और 40 एकदिवसीय खेले हैं। ख्वाजा ने टेस्ट मैचों में 4 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। टेस्ट में इस बल्लेबाज के नाम 13 शतक हैं। वहीं एकदिवसीय में उन्होंने पंद्रह सौ से अधिक रन बनाये हैं।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति: आईओसी ने रूस, बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंधों को रखा जारी

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने रूसी ओलंपिक समिति (आरओसी) के अध्यक्ष स्टानिस्लाव पॉज्न्याकोव की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें रूसी और बेलारूसी राज्य और सरकारों के खिलाफ प्रतिबंधों पर अपने रुख की पुष्टि की गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने आईओसी के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा, रूसी और बेलारूसी राज्य और सरकारों के खिलाफ प्रतिबंधों से समझौता नहीं किया जा सकता है।प्रवक्ता ने आगे कहा, 9 दिसंबर 2022 को हाल ही में हुई ओलंपिक शिखर सम्मेलन की बैठक में उनकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई है। यहां रूस या बेलारूस में आईएफ और एनओसी द्वारा कोई अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन या समर्थन नहीं किया गया।प्रवक्ता ने आगे कहा, इन देशों का कोई भी झंडा, गान, रंग या कोई अन्य पहचान किसी भी खेल आयोजन या बैठक में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण स्थल भी शामिल है। साथ ही किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन या बैठक के लिए किसी भी रूसी और बेलारूसी सरकार या राज्य के अधिकारी को आमंत्रित या मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए।पॉज्न्याकोव ने पिछले हफ्ते आईओसी द्वारा रूसी एथलीटों को अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति देने के कदम का स्वागत किया क्योंकि आईओसी ने कहा कि सख्त परिस्थितियों में प्रतियोगिता में एथलीटों की भागीदारी के लिए एक मार्ग का पता लगाया जाना चाहिए। इस बीच, आरओसी प्रमुख रूसी एथलीटों पर लगाए गए अतिरिक्त शर्तों के खिलाफ थे।

करेन को जश्न मनाना भारी पड़ा आईसीसी ने जुर्माना लगाया

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करेन पर जुर्माना लगाया है। करेन पर यह जुर्माना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में विकेट मिलने के बाद जश्न मनाने के कारण लगाया है। आईसीसी ने करेन को फटकार लगाने के साथ ही मैच फीस का 15 फीसदी जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उन्हें एक नकारात्मक अंक भी दिया। करेन पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा को आउट करने के बाद अतिउत्साह में पिच पर उनके बेहद करीब पहुंच गए थे। आईसीसी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आईसीसी नियम के अनुसार मैच के दौरान अभद्र भाषा या आक्रामक संकेतों का उपयोग प्रतिबंधित है इस प्रकार का संकेत किसी बल्लेबाज के आउट होने पर करने से वह आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए भड़क सकता है। जिस मैच में यह घटना हुई वह दक्षिण अफ्रीका के ब्लोएमफोंटेन में खेला जा रहा था। इसमें दक्षिण अफ्रीकी पारी के 28वें ओवर में बावुमा शतक लगाकर आउट हुए। बावुमा को आउट करने के बाद करेन जश्न मनाते हुए उनके बेहद करीब पहुंच गए। बाद में करेन ने मैच रेफरी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीकी टीम जीती थी।

बबीता फोगाट कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की जांच के लिए गठित समिति में शामिल

नई दिल्ली । महिला पहलवान बबीता फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच के लिए गठित समिति में शामिल किया है। बबीता इस समिति की अध्यक्ष एम सी मेरीकोम का सहयोग करेंगी। खेल मंत्रालय द्वारा गठित यह समिति डब्ल्यूएफआई और उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के अलावा धमकी देने और वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच कर रही है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर ये आरोप विनेश फोगाट सहित कई पहलवानों ने लगाये हैं। खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बबीता फोगाट को खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति में शामिल किया गया है यह समिति फिलहाल महासंघ का दिन प्रतिदिन का कामकाज भी देखेगी। इस समिति में महान मुक्केबाज मेरीकोम पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे पूर्व साइ अधिकारी राधिका श्रीमन और टारगेट ओलिम्पिक पोडियम योजना के पूर्व सीईओ राजेश राजगोपालन भी शामिल किये गये हैं। पहलवानों की मांग पर कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने इस समिति का गठन किया था पर पहलवान संतुष्ट नहीं थे। किये जाने के बाद पहलवानों ने जंतर मंतर पर 3 दिन से चल रहा अपना धरना खत्म किया था। बाद में हालांकि पहलवानों ने कहा था कि समिति का गठन करने से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई थी।

पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण अलेक्जेंडर ज्वेरेव को नहीं करना पड़ेगा अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना

(एजेंसी)

वर्ष 2020 यूएस ओपन चैंपियन और जर्मन टेनिस स्टार अलेक्जेंडर ज्वेरेव को उनकी पूर्व प्रेमिका द्वारा लगाए गए घरेलू दुर्व्यवहार के आरोपों में किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।ज्वेरेव की पूर्व प्रेमिका ओलेआ शारिपोवा द्वारा घरेलू शोषण के आरोपों के बाद अक्टूबर 2021 में एटीपी द्वारा जांच शुरू की गई थी। यह जांच द लेक फॉरेस्ट ग्रुप (एलएफजी) द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व संस्थापक और मुख्य कार्यकारी जी माइकल वर्डेन और जेनिफर मैकोवजक ने किया था। जांच ने शारिपोवा और ज्वेरेव दोनों के ऑडियो और तस्वीरों सहित सबमिशन की समीक्षा की। इसमें तीसरे पक्ष के फोरेंसिक विशेषज्ञ के माध्यम से ज्वेरेव के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकाली गई सामग्री शामिल थी। एलएफजी ने सोशल मीडिया सहित तीसरे पक्ष के गवाहों और सार्वजनिक रिकॉर्ड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की भी समीक्षा की और अपनी पूरी रिपोर्ट एटीपी को सौंपी। एटीपी ने मंगलवार को अपने ब्यान में कहा, शारिपोवा, ज्वेरेव और अन्य साक्षात्कारकर्ताओं के बयानों के अलावा, विश्वसनीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी रिपोटरें की कमी के आधार पर, जांच दुरुपयोग के आरोपों को साबित करने में असमर्थ थी या एटीपी के ऑन-साइट अपराधों या खिलाड़ी के बड़े अपराधों के नियमों का उल्लंघन निर्धारित करने में असमर्थ थी।

अय्यर की जगह सूर्यकुमार या शुभमन को मिला सकता है अवसर

मुम्बई ।

बल्लेबाज श्रेयय अय्यर फिट नहीं होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गये हैं। ऐसे में उनकी जगह पर मध्यक्रम में टीम प्रबंधन आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल में से किसी एक को अवसर दे सकता है। अय्यर पीठ में खिंचाव से अभी तक नहीं उबरे हैं और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। माना जा रहा है कि वह अगले कुछ समय तक नहीं खेल पायेंगे। सूर्यकुमार ने अबतक टी20 में शानदार प्रदर्शन कर अपने को साबित किया है। वहीं शुभमन ने एकदिवसीय क्रिकेट में दमदार पारियां खेली हैं। अय्यर ने पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला में 2–0 की जीत के दौरान भी शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में उनकी जगह पर शामिल होने वाले बल्लेबाज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान लोकेश राहुल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इनके बाद तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा और चौथे नंबर पर विराट कोहली खेलेंगे। शुभनन के मामले में टेस्ट क्रिकेट में नियमित रूप से खेलने और लाल गेंद का करियर मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरू करने के कारण उनका पलड़ा भारी रहेगा। वहीं स्पिन की अनुकूल पिचों पर स्पिनरों के खिलाफ सूर्यकुमार के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भी अवसर मिल सकता है। सूर्यकुमार की दावेदारी इसलिए पक्की है क्योंकि वह नाथन लियोन की स्पिन के खिलाफ प्रभावी रहेंगे। दूसरी और शुभमन तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पर्यटन

केरल राज्य कई नदियों और पर्वत-पहाड़ियों से घिरा हुआ एक अनोखा पर्यटक स्थल है। जहां प्रतिवर्ष लाखों देशी-विदेशी पर्यटक यहां का सौंदर्य निहारने के लिए आते है। खास तौर पर यहां का विशिष्ट वन्य जीवन और जल प्रपात मन को मंत्रमुग्ध कर देते है।

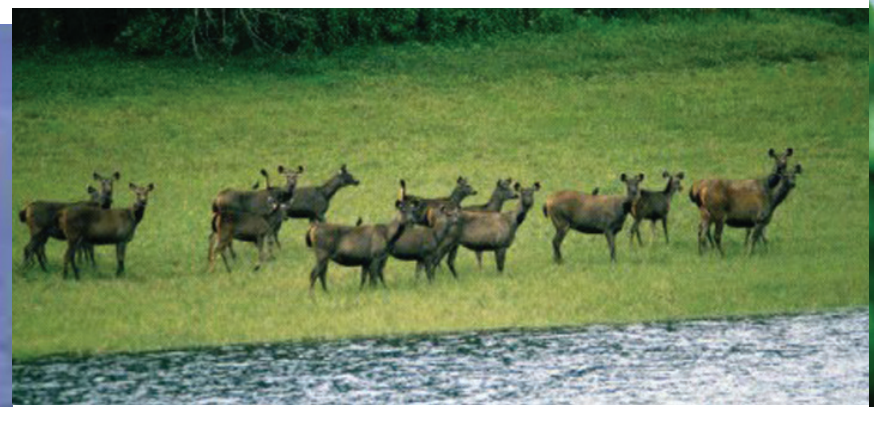

एक अनोखा पर्यटक स्थल

केरल नेशनल पार्क

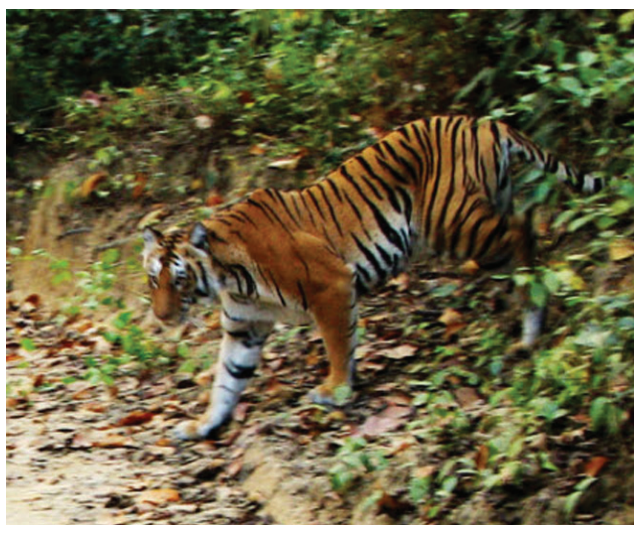

आइए जानते है केरल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। जिनमें प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मुख्य तौर इर्रावीकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क, इडुकी नेशनल पार्क आदि कई छोटे-बड़े नेशनल पार्क आते हैं। गौरतलब है कि विश्व भर में केरल वन्यजीवों की आरामगाह के रूप में भी प्रसिद्ध है।

इर्रावीकुलम

केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इर्रावीकुलम नेशनल पार्क मुख्य रूप से नीलगाय तराह (हेमीट्रेगस हाइलो क्रिकस) के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया पार्क है। ज्ञात हो कि नीलगाय तराह एक दुर्लभ पशु है, जो सिर्फ हिमालय के ठंडे इलाकों में पाया जाता है।

वर्ष 1978 में इस वन्यजीव पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। 97 वर्ग किलोमीटर में फैला पेड़-पौधों से भरपूर, घास के बड़े मैदान से युक्त इर्रावीकुलम पार्क के उत्तरी सिरे को, जो तमिलनाडु राज्य को छूता है, उसे अन्नामलाई के नाम से विश्व में पहचाना जाता है। यहां से अनामुड्डी हिमालय की 2695 मीटर की सबसे ऊंची दक्षिणी चोटी पूरी भव्यता के साथ इस अभयारण्य में दिखाई देती है। यहां नील गिरी लंगूर, लायन टेल्ड मेकाक, चीते, बाघ आदि कई दुर्लभ प्रकार के जीव-जंतु और वनस्पतियां भी पाई जाती है।

साइलेंट वैली

केरल के पश्चिमी छोर पर कुंडलई हिल्स पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। मुख्य रूप से हाथी, बाघ और शेर, पूंछ वानर जैसे जीवों के साथ-साथ कई दुर्लभ किस्मों की औषधि और पेड़-पौधों के कारण यह पार्क प्रसिद्ध है। यहां का अनुकूल वातावरण और छोटी-बड़ी नदियां एवं पहाड़ इसे वन्यजीवों के लिए आरामगाह बनाते हैं।

पेरियार ः केरल के पश्चिमी छोर पर पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। यह मुख्य तौर पर बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक नेशनल पार्क है, जो दुनिया भर के नेशनल पार्क में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसे अंग्रेजों द्वारा सन् 1895 में अधिगृहीत किया गया था तथा अंग्रेजों ने उस वक्त यहां एक कृत्रिम झील और बांध का निर्माण भी किया था। पेरियार नेशनल पार्क 777 वर्ग किलोमीटर में फैला एक आरक्षित वन है। इसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पेरियार नदी के नाम पर ही इसे पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, जो पश्चिमी घाट की ऊंची श्रृंखला पर बसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का यह एकमात्र ऐसा अभयारण्य है, जहां हाथियों को केवल एक नाव की दूरी से देखा जा सकता है और उनकी तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। यहां के वन्य जीवन और सुंदरता के कारण यह विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है।

वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी

बाघ और तेंदुए के लिए वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह बांदीपुर नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। इस अभयारण्य में हिरण, भालू, हाथी, बाघ-चीते, जंगली-सीएट बिल्ली, बंदर, जंगली कुत्ते, भैंसे ऐसे कई प्रकार के वन्य जीव-जंतु पाए जाते हैं। यहां पर अपार जैव विविधता है। यह अभयारण्य नील गिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अविभाज्य भाग है, जिसे इस क्षेत्र की जैविक विरासत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

यहां पर विशेष पाए जाने वाले सरीसृप हैं मॉनिटर छिपकली। साथ ही अनेक प्रकार के सांप यहां देखे जा सकते हैं। यहां पक्षियों में खास तौर पर मोर, उल्लू, कठफोड़वा, जंगली फाउल, बैबलर, कुक्कु आदि मुख्य हैं।

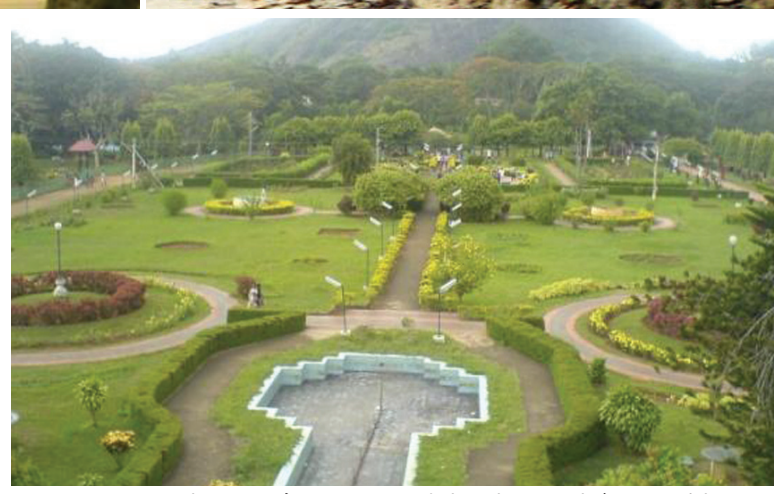

इडुकी

केरल के दक्षिण भारतीय राज्य में बसा यहां के सर्वोत्तम स्थानों में से एक है इडुकी नेशनल पार्क। जो वन्य जीवों के लिए मुख्य तौर पर माना जाता है। यहां बाघ, हाथी, भैंस, भालू, जंगली सुअर, सांभर तथा जंगली कुत्ते-बिल्लियां आदि बड़े-बड़े झुंडों में घूमते नजर आते हैं। इस पार्क में जंगली फाउल, काली बुलबुल, लाफिंग थ्रश, कठफोड़वा, मैना आदि कुछ महत?वपूर्ण पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। यहां पर सांपों की अनेक प्रजातियों में विशेष कोबरा, वाइपर, क्रेट और कई विषरहित साप भी यहां पाए जाते हैं। कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि अगर आपने अभी तक केरल के नेशनल पार्क नहीं देखे हैं, तो एक बार जरूर जाइए। यहां के कई प्रजाति के वन्य जीवों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाएंगे।

जानिए प्राचीन शहर यरूशलम को

भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच इसराइल की सीमा पर बसा यरूशलम एक शानदार शहर है। शहर की सीमा के पास दुनिया का सबसे ज्यादा नमक वाला डेड-सी यानी मृत सागर है। कहते हैं यहां के पानी में इतना नमक है कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता और इसके पानी में मौजूद नमक के कारण इसमें कोई डूबता भी नहीं है।मध्यपूर्व का यह प्राचीन नगर यहूदी, ईसाई और मुसलमान का संगम स्थल है। उक्त तीनों धर्म के लोगों के लिए इसका महत्व है, इसीलिए यहां पर सभी अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। जेहाद और क्रूसेड के दौर में सलाउद्दीन और रिचर्ड ने इस शहर पर कब्जे के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ईसाई तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए इसी दौरान नाइट टेम्पलर्स का गठन भी किया गया था।इसराइल का एक हिस्सा है गाजा पट्टी और रामल्लाह। जहां फिलिस्तीनी मुस्लिम लोग रहते हैं और उन्होंने इसराइल से अलग होने के लिए विद्रोह छेड़ रखा है। यह लोग यरूशलम को इसराइल के कब्जे से मुक्त कराना चाहते हैं। अंततः इस शहर के बारे में जितना लिखा जाए कम है। काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या, ग्रीस, बाली, श्रीनगर, जाफना, रोम, कंधहार आदि प्राचीन शहरों की तरह ही इस शहर का इतिहास भी बहुत महत्व रखता है।

प्राचीन और नया शहर

माउंट ऑफ ओलिब्स पर खड़े होकर आप सामने यरूशलम के प्राचीन शहर को देखते हैं, तो उसके मनोरम और भव्य दृश्य का नजारा देख आप मंत्रमुग्ध होकर सोचना बंद कर देते हैं। ओलिब्स पहाड़ी से सुंदर गुंबद और गुंबदों के पीछे दीवार नजर आती है। एक वर्ग किलोमीटर की पहाड़ी दीवारों से घिरा हजारों सालों का इतिहास लिए यह शहर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की आस्था का केंद्र हैं।

इतिहास और विवाद

हिब्रू में लिखी बाइबिल में इस शहर का नाम 700 बार आता है। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि यही धरती का केंद्र है। राजा दाऊद और सुलेमान के बाद इस स्थान पर बेबीलोनियों तथा ईरानियों का कब्जा रहा फिर इस्लाम के उदय के बाद बहुत काल तक मुसलमानों ने यहां पर राज्य किया। इस दौरान यहूदियों को इस क्षेत्र से कई दफे खदेड़ दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसराइल फिर से यहूदी राष्ट्र बन गया तो यरूशलम को उसकी राजधानी बनाया गया और दुनिया भर के यहूदियों को पुनः यहां बसाया गया। यहूदी दुनिया में कहीं भी हों, यरूशलम की तरफ मुंह करके ही उपासना करते हैं।

ऐतिहासिक म्यूजियम व स्मारक

धार्मिक स्थलों के अलावा यहां प्राचीन एवं धार्मिक ग्रंथों का द इसराइल म्यूजियम है। इसराइल का होलोकॉस्ट म्यूजियम जिसे याद वशेम कहा जता है जिसका खासा महत्व है। यहां पर यरूशलम के इतिहास से संबंधित दस्तावेज और शहीदों के स्मारक व स्मृति चिह्नों आदि के बारे में जानकारी है। दोनों ही म्यूजियम का इतिहास बहुत पुराना है।

यरूशलम के जंगल

मुस्लिम इलाके में स्थित 35 एकड़ क्षेत्रफल में फैले नोबेल अभयारण्य में ही अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक, फव्वारे, बगीचे, गुंबद और प्राचीन इमारतें बनी हुई हैं। इसके अलावा छोटे से गॉर्डन ऑफ गेथेमिन की खूबसूरती भी देखने लायक है। इसके अलावा याद वशेम का इलाका भी यरूशलम के जंगल के नाम से प्रसिद्ध है।

पवित्र परिसर

किलेनुमा चाहरदीवारी से घिरे पवित्र परिसर में यहूदी प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। इस परिसर की दीवार बहुत ही प्राचीन और भव्य है। यह पवित्र परिसर ओल्ड सिटी का हिस्सा है। पहाड़ी पर से इस परिसर की भव्यता देखते ही बनती है। इस परिसर के ऊपरी हिस्से में तीनों धर्मों के पवित्र स्थल हैं। उक्त पवित्र स्थल के बीच भी एक परिसर है। यरूशलम में लगभग 1204 सिनेगॉग, 158 गिरजें, 73 मस्जिदें, बहुत-सी प्राचीन कब्रें, 2 म्यूजियम और एक अभयारण्य है। इसके अलावा भी पुराने और नए शहर में देखने के लिए बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। यरूशलम में जो भी धार्मिक स्थल हैं, वे सभी एक बहुत बड़ी-सी चौकोर दीवार के आसपास और पहाड़ पर स्थित है। दीवार के पास तीनों ही धर्म के स्थल हैं। यहां एक प्राचीन पर्वत है जिसका नाम जैतून है। इस पर्वत से यरूशलम का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। इस पर्वत की ढलानों पर बहुत-सी प्राचीन कब्रें हैं। यरूशलम चारों तरफ से पर्वतों और घाटियों वाला इलाका नजर आता है।

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पूर्व पीएम डा. मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में 'लाइफ टाइम अचीवमैंट ऑनर' से सम्मानित किया

लंदन। पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए हाल में 'इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स' ने लंदन में लाइफटाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया है। पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में इस सम्मान की घोषणा की गई। 'नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूनाइटेड किंगडम' (एनआईएस एयू-यूके) बाद में नई दिल्ली में डा मनमोहन सिंह को इससे सम्मानित करेगा। एनआईएसएयू-यूके द्वारा 'इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स' ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (डीआईटी) और 'ब्रिटिश काऊंसिल इन इंडिया' के सहयोग से ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल कर जीवन में उपलब्धि अर्जित करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को दिया जाता है।

उत्सर्जन कम होने के बावजूद 10-15 साल में 1.5 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पार कर जाएगा तापमान

बोस्टन। उत्सर्जन कम होने के बावजूद दुनिया में 10 से 15 साल के भीतर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार कर जाएगा। एक अध्ययन में यह अनुमान जताया गया है। अध्ययन के अनुसार परिणामों का अनुमान जताने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल किया गया। अध्ययन के अनुसार यदि अगले कुछ दशकों में उत्सर्जन अधिक रहता है तो इस सदी के मध्य तक पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में पृथ्वी के औसतन दो डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होने का अनुमान है। इसके साथ ही इसके 2060 तक उस सीमा तक पहुंचने का भी अनुमान है। इस अध्ययन में दुनियाभर के हालिया तापमान अवलोकनों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन का अनुमान जताया गया है। अध्ययन के लेखक अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक जलवायु वैज्ञानिक नूह डिफेनबॉघ हैं। डिफेनबॉघ ने कहा भविष्य के बारे में अनुमान जताने के लिए जलवायु प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर निर्भर एक पूरी तरह से नए दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हम पुष्टि करते हैं कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा पार करने की दहलीज पर है। उन्होंने कहा हमारे एआई मॉडल से यह स्पष्ट है कि पहले से ही धरती पर तापमान अधिक है और यदि इसके शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने में एक और आधी शताब्दी लगती है तो इसके दो डिग्री सेल्सियस को पार करने का अनुमान है।

संयुक्त अरब अमीरात के अल मिनहद जिले का नाम अब होगा हिंद शहर

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने रविवार को अल मिनहद जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर 'हिंद शहर' कर दिया। अमीरात की आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम ने यह जानकारी दी। शहर को चार क्षेत्रों में बांटा गया है और इसमें संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों के घर हैं। डब्ल्यूएएम ने बताया कि शहर में चार क्षेत्र हिंद-1 हिंद-2 हिंद-3 और हिंद-4 शामिल हैं और यह 83.9 किमी के क्षेत्र में फैला है। हिंद शहर अमीरात रोड दुबई अल ऐन रोड और जेबेल अली-लेहबाब रोड जैसे प्रमुख सड़कों से जुड़ा हुआ है। दुबई शासक के निर्देशों के अनुसार अल मिनहद क्षेत्र और उसके पड़ोसी क्षेत्रों का नाम बदलकर 'हिंद शहर' कर दिया गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब दुबई में किसी जगह का नाम बदला गया है। इससे पहले 2010 में संयुक्त अरब अमीरात के तत्कालीन राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर बुर्ज दुबई का नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया था। 13 मई 2022 को उनका निधन हो गया था। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अल मिनहद जिले का नाम बदलकर 'हिंद शहर' कर दिया। वे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री होने के साथ-साथ दुबई के शासक भी हैं। वह संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मकतूम के तीसरे बेटे हैं। 2006 में अपने भाई मकतूम की मृत्यु के बाद मोहम्मद ने देश के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक के रूप में पदभार संभाला था। अल मकतूम की पहचान 'दुनिया के सबसे प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक' के रूप में की जाती है।

पूर्व मिलिट्री जनरल ने खोली अमेरिका की पोल ड्रैगन से लड़ने को तैयार नहीं

वॉशिंगटन। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच पूर्व मिलिट्री जनरल ने बड़ी चेतावनी दी है। रिटायर्ड अमेरिकी जनरल जैक कीन ने कहा कि अमेरिकी सेना चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और चीन के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों ही देशों में ताइवान दक्षिण चीन सागर तिब्बत हॉन्ग कॉन्ग उइगर जैसे कई मुद्दों पर विवाद है। इस बीच अमेरिकी वायु सेना के एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख ने अधिकारियों को मेमो भेजकर चीन के साथ युद्ध की भविष्यवाणी की है। अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद माइकल मैककॉल ने भी जनरल माइक मिन्हान के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि ताइवान के मुद्दे पर चीन से संघर्ष की आशंका काफी ज्यादा है। वहीं पूर्व अमेरिकी जनरल जैक कीन ने कहा कि अगर चीन के साथ कोई संघर्ष हुआ तब अमेरिका तैयार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उतने तैयार नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। हमारे पास इस क्षेत्र में एक प्रभावी सैन्य प्रतिरोध नहीं है। चीन के पास अमेरिका से अधिक जहाज अधिक विमान और अधिक मिसाइलें हैं। जनरल कीन ने ताइवान के भविष्य पर चेतावनी देकर रूस-यूक्रेन युद्ध से तुलना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ताइवान की सैन्य जरूरतों को जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों के पास मित्र देशों के कई हथियारों की डील लटकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि में उस सिस्टम को सुधारना होगा जिससे मदद को जल्द से जल्द भेजा जा सके। ताइवान ने 2019 में अमेरिका के साथ एम1ए2 टैंक की डील की थी। लेकिन अब अमेरिका ने पहले यूक्रेन और फिर पोलैंड को टैंक भेजने का निर्णय लिया है। कीन ने कहा कि हमें ताइवान की मदद करनी है और हमें अपनी समस्या खुद सुलझानी है। वास्तव में हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें जोखिम को दूर करना होगा और हमेशा तैयार रहना होगा। ऐसे में ही हम युद्ध को रोक सकते हैं।

चीन ने लड़कियों को बिनब्याही मां बनने की कानूनी मंजूरी दी

-देश में गिरती जन्म दर से चिंतित शी सरकार

बीजिंग। चीन ने अपने देश में लड़कियों के बिनब्याही मां बनने को कानूनी मंजूरी दे दी है। इस कानून को पायलट प्रोजक्ट के तौर पर अभी सिर्फ सिचुआन प्रांत में लागू किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश में गिरती जन्म दर को कम करने के नवीनतम प्रयास के तौर पर कानून को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को परिवार बढ़ाने और विवाहित जोड़ों के लिए सरकारी मदद को तेज किया जाएगा। चीन में अभी तक केवल विवाहित महिलाओं को ही कानूनी रूप से बच्चे को जन्म देने की अनुमति है। लेकिन हाल के वर्षों में विवाह और जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट से चीनी सरकार के हाथ-पांव फूले हुए हैं। एक समय ऐसा भी था जब चीन ने बढ़ती आबादी को रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू किया था। 15 फरवरी से विवाहित जोड़े और संतान की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चीन के पांचवें सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत में सरकार के साथ पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें बच्चों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। इसके बाद एक व्यक्ति जितना चाहे उतने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सिचुआन के स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य दीर्घकालिक और संतुलित जनसंख्या विकास को बढ़ावा देना है। अब तक आयोग ने केवल उन विवाहित जोड़ों को अनुमति दी थी जो दो बच्चों तक स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराना चाहते थे। चीन की आबादी पिछले साल छह दशकों में पहली बार घटी है। इस गिरावट से भविष्य में चीनी जनसांख्यिकी को लेकर संकट खड़ा हो गया है। इसके बाद चीनी अधिकारी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और उपाय की नई-नई नीतियां बना रहे हैं। अभी तक अगर विवाहित जोड़ा बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है तब उस इलाज के खर्च में छूट मिलती है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन भी दिया जाता है।

कोंगो पहुंचे पोप फ्रांसिस के सम्मान में नाचते गाते हुए लोग।

निकी हेली की 2024 में व्हाइट हाउस के लिए 15 फरवरी से अभियान शुरू करने की योजना

कोलंबिया। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ निकी हेली राष्ट्रपति पद के लिये अपने अभियान को आधिकारिक रूप देती नजर आ रही हैं। दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर के समर्थकों को बुधवार को चार्ल्सटन में 15 फरवरी को एक कार्यक्रम के लिए एक ईमेल आमंत्रण मिलेगा, जिसमें वह अपने अभियान की घोषणा करने की योजना बना रही है। इस बारे में

जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने यह बताया लेकिन वह इस पर आधिकारिक तौर पर बोलने के लिये अधिकृत नहीं है। हेली की योजनाओं की खबर सबसे पहले 'द पोस्ट एंड कूरियर ऑफ चार्ल्सटन' द्वारा दी गई थी। हेली (51) ने छह सालों तक साउथ कैरोलिना की गवर्नर के तौर पर काम किया और फिर उसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के तौर पर सेवाएं दे चुकी हैं। अगला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होना है।

डोभाल की अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के सहयोग को गति देने का आधार तैयार किया: भारतीय दूतावास

वाशिंगटन (एजेंसी)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित के. डोभाल ने अपनी यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं के माध्यम से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग को गति देने का आधार तैयार किया जो कि वास्तव में एक व्यापक व वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की परिपक्वता का परिचायक है। यहां भारतीय दूतावास ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में भारतीय दूतावास ने कहा, ''इस यात्रा के दौरान हुईं चर्चाएं अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग को गहरा करने का आधार स्थापित करती हैं और वास्तव में भारत-अमेरिका व्यापक, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की परिपक्वता को दर्शाती हैं।'' डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन ने यहां व्हाइट हाउस में अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 'इनीशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी' (आईसीईटी) की पहली उच्च-स्तरीय बैठक की।

इसके अलावा डोभाल ने कई शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। डोभाल ने 30 जनवरी से एक फरवरी तक की यात्रा के दौरान, आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सरकार, कांग्रेस, उद्योग, अकादमिक, अनुसंधान से संबद्ध अमेरिकी नीति निर्माताओं और हितधारकों के साथ बैठकें कीं। सुलिवन के अलावा डोभाल ने अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिली, अमेरिका की उप रक्षा मंत्री डॉ. कैथलीन हिक्स, शीर्ष सासदों और उद्योग जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात की। उनकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलने की योजना है।

डोभाल और सुलिवन ने 'इनीशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी' (आईसीईटी) की जो पहली उच्च-स्तरीय बैठक की, उसका मई 2022 में तोक्यो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच बैठक के बाद पहली बार एक संयुक्त बयान में उल्लेख किया गया था। इसका मकसद दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना तथा उसे विस्तार देना है। दूतावास ने कहा, ''आईसीईटी का मकसद प्रौद्योगिकी श्रृंखलाओं का निर्माण करके और वस्तुओं के सह-विकास तथा सह-उत्पादन का समर्थन करके दोनों देशों के बीच विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी स्थापित करना है। इसका मकसद स्थायी तंत्र के माध्यम से विनियामक प्रतिबंधों, निर्यात नियंत्रण और बाधाओं को दूर करना भी है।''

बैठक के दौरान, अमेरिकी पक्ष ने विधायी परिवर्तनों के प्रयासों सहित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत के लिए निर्यात बाधाओं को कम करने का आश्वासन दिया। भारत के प्रतिनिधिमंडल में डोभाल के अलावा अमेरिका में भारत के राजदूत, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष, दूरसंचार विभाग में सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के महानिदेशक शामिल थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रशासक, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक, नेशनल स्पेस काउंसिल के कार्यकारी सचिव और विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दूतावास ने बताया कि बैठक में भारत के अर्द्धचालक (सेमीकंडक्टर) अभियान के लिए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) और यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए) को शामिल करते हुए एक कार्यबल गठित करने पर सहमति बनी, ताकि निकट भविष्य के अवसरों की पहचान करने और अर्द्धचालक पारिस्थितिकी के दीर्घकालिक विकास की सुविधा के लिए तैयारी हो सके। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में दोनों पक्ष पारस्परिक हित की प्रमुख वस्तुओं के संयुक्त उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए। साथ ही अगली पीढ़ी के दूरसंचार में, भारत की लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता को देखते हुए दोनों पक्ष विश्वसनीय स्त्रोतों का उपयोग करते हुए एक सार्वजनिक-निजी संवाद शुरू करने पर सहमत हुए, जिसमें 5जी/6जी और ओआरएएन को भी शामिल किया जाएगा।

100 हुई पेशावर मस्जिद विस्फोट में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पेशावर की एक मस्जिद में 30 जनवरी को नमाज के दौरान किए गए आत्मघाती विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है 200 से अधिक लोग जख्मी हैं जिनमें कई की हालत नाजुक है। इस घटना पर प्रतिक्रिया करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत में प्रार्थना के दौरान पूजा करने वाले नहीं मारे जाते हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता का आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए अपने घर को व्यवस्थित करने का समय है। उन्होंने 2010-2017 के बीच की आतंकी घटनाओं को याद करते हुए कहा यह युद्ध पीपीपी के कार्यकाल में स्वात से शुरू हुआ था और यह पीएमएल-एन के पिछले कार्यकाल के दौरान समाप्त हुआ और देश में कराची से स्वात तक शांति कायम हुई थी।

उन्होंने कहा लेकिन अगर आपको याद है डेढ़ या दो साल पहले हमें इसी हॉल में दो तीन बार एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इन लोगों के साथ बातचीत की जा सकती है और उन्हें शांति की ओर लाया जा सकता है। आसिफ ने कहा इस मामले पर अलग-अलग राय सामने आई थी लेकिन इसके बावजूद कोई 'अंतिम और ठोस फैसला' नहीं लिया गया। उन्होंने कहा अफ़ग़ानों के पाकिस्तान में आकर बसने के बाद हज़ारों लोग बिना नौकरी के रह गए थे। आसिफ ने यह भी कहा कि पहला सबूत तब सामने आया जब स्वात के लोगों ने वहां फिर से बस रहे लोगों का विरोध किया।

इस बीच पेशावर के कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर (सीसीपीओ) एजाज खान ने 'जियो टीवी' को बताया कि विस्फोट स्थल से संदिग्ध आत्मघाती हमलावर का सिर बरामद किया गया है। संदिग्ध हमलावर की पहचान मोहमंद एजेंसी के सलीम खान के 37 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अयाज के रूप में हुई है। खान ने कहा 'यह संभव है कि हमलावर विस्फोट से पहले ही पुलिस लाइन में मौजूद था और हो सकता है कि उसने प्रवेश करने के लिए एक आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कहा आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) मामले की जांच कर रहा है।

दिन-ब-दिन पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है टीटीपी, पेशावर की मस्जिद के बाद अब पुलिस स्टेशन पर किया जबरदस्त अटैक

इस्लामाबाद (एजेंसी)। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इन दिनों आतंकवाद की भी मार झेल रहा है। जिस आतंकवाद को बरसों तक उसने पाला पोसा अब वहीं उसके गले की फांस बनता जा रहा है। पेशावर घातक आत्मघाती बम विस्फोट में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस आतंकी वारदात के बाद अब मियांवाली में एक पुलिस स्टेशन पर 31 जनवरी की रात प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने हमला कर दिया। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने देर रात दावा किया कि हमले को नाकाम कर दिया गया है। आतंकी संगठन ने अब तक खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में पुलिस स्टेशनों और चेक पोस्टों को निशाना बनाया था। देश में आतंकवाद के पुनरुत्थान के बाद पहली बार पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर अपनी नजरें जमाई हैं।

पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक डॉ उस्मान अनवर ने डॉन से पुष्टि की कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीटीपी से जुड़े सशस्त्र हमलावरों ने पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि टीटीपी के खिलाफ एक बड़े अभियान के लिए लाहौर पुलिस और पंजाब सीटीडी के अलावा तीन क्षेत्रों मियांवाली, डेरा गाजी खान और सरगोधा से पुलिस दल मियांवाली पहुंचे। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला रात करीब 9 बजे शुरू हुआ, जब आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से मकरवाल पुलिस स्टेशन पर भारी गोलीबारी की। इसके परिणामस्वरूप भारी गोलीबारी हुई, क्योंकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जो दो घंटे तक चली।

हालांकि, हमले के दौरान पुलिस कर्मियों के किसी भी घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

मियांवाली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस स्टेशन में तैनात कर्मियों ने हमले को टालते हुए तेजी से प्रतिक्रिया की। अधिकारी ने कहा कि इसाखेल तहसील में मकरवाल, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है, जो कोयला खदानों के लिए जाना जाता है।

बीबीसी डाक्यूमेंट्री विवाद पर भारत के साथ खड़ा हुआ रूस ब्रिटिश मीडिया पर लगाया सूचना युद्ध छेड़ने का आरोप

मास्को (एजेंसी)। गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवाद के बीच रूस ने बीबीसी पर अलग-अलग मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि यह बीबीसी द्वारा विभिन्न मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत है न केवल रूस के खिलाफ बल्कि सत्ता के अन्य वैश्विक केंद्रों के खिलाफ भी स्वतंत्र नीति। विदेश मंत्रालय द्वारा भारत में डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के हफ्तों बाद रूसी समर्थन आया है। दो भाग की डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गुजरात दंगों के कुछ पहलुओं की जांच करने का दावा किया गया है। ज़खारोवा ने कहा बीबीसी ब्रिटिश प्रतिष्ठान के भीतर भी लड़ रहा है। इसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए।

केंद्र ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री इंडिया- द मोदी क्वेश्चन के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को एक प्रोपेगेंडा के रूप में खारिज कर दिया है जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। रूस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के वृत्तचित्र को स्वतंत्र नीति का अनुसरण करने वाली शक्ति के वैश्विक केंद्रों के खिलाफ सूचना युद्ध के रूप में वर्णित किया है। मॉस्को में एमएफए साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रूसी टिप्पणी और भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के सवाल के जवाब में प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा मुझे यकीन नहीं है कि यह एक सवाल है हमारे लिए।

यूक्रेन: सेना में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है; हजारों संभाल रही हैं अग्रिम मोर्चा

एब्रिस्विथ। (द कन्वरसेशन) (एजेंसी)। क्रीमिया तथा पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर 2014 में रूस द्वारा कब्जा करने की शुरूआत के बाद से यूक्रेन की सेना में हजारों महिलायें स्वेच्छा से शामिल हुयी हैं। पिछले नौ साल से अधिक समय में यूक्रेन की सेना में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या दोगुने से अधिक हो गयी है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूरी ताकत के साथ हमला किये जाने के बाद यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिये महिलाओं के बीच एक लहर चल पड़ी है। ऐसे तो सोवियत संघ से 1991 में आजाद होने के बाद से ही यूक्रेन के सशस्त्र बल में महिलायें अपनी सेवा दे रही हैं, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका 2014 की लड़ाई की के बाद से शुरू हुयी।

महिलाओं ने 2016 में लड़ाकू भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और 2022 में सभी सैन्य भूमिकाओं को महिलाओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि, गैर-लड़ाकू

भूमिका में शामिल कई महिलाएं, जैसे कि मेडिक्स, भी संघर्षरत और युद्ध के मोर्चे पर डटे अपने पुरुष और महिला सहयोगियों के समान ही खतरों और कठिनाइयों में हैं। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार के अनुसार, 2022 की गर्मियों तक 50 हजार से अधिक महिलाओं को सेना में विभिन्न भूमिकाओं में लिया गया है, इनमेंसे करीब 38 हजार महिलायें वर्दीधारी हैं। उनके अनुसार महिलायें अब अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में भी शामिल हैं। सशस्त्र बलों में शामिल महिलाओं को रूसियों द्वारा युद्धबंदी बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मेडिक्स यूलिया पेवेस्का को तीन महीने की कैद हुई थी।

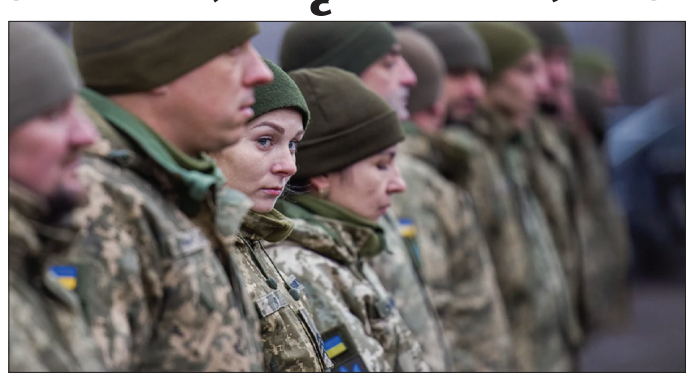

पेवेस्का ने बताया, ''हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह बेहद कठिन और कठोर था।'' पितृसत्तात्मक सोच बदल रही है- यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां, पितृसत्तात्मक परंपरा बेहद मजबूत है, खास तौर से रक्षा क्षेत्र में। लेकिन यूक्रेन की महिला सैनिकों को यूक्रेन का समाज और देश का राजनीतिक नेतृत्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर स्वीकार कर रहे हैं। सेना और समाज में महिलाओं की उपस्थिति को पहचान का एक संकेत तब मिला जब 2021 में नेशनल डिफेंडर्स डे का नाम बदल कर 'डे ऑफ मेन एंड वूमन डिफेंडर्स ऑफ यूक्रेन' कर दिया गया। और दूसरे भी संकेत हैं- रक्षा मंत्रालय अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महिला सैनिकों की तस्वीर अब नियमित तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

यूक्रेन की महिला सैनिक भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और वह अपने सैन्य अनुभव के बारे में बातचीत करती रहती हैं। अक्टूबर 2022 तक यूक्रेन की सेना में आठ हजार महिला अधिकारी हैं और यूक्रेन की एक उप रक्षा मंत्री महिला है। लेकिन यूक्रेनी सशस्त्र बलों में महिलाओं की उपस्थिति बिना विवाद के नहीं रही है। कुछ विश्लेषकों ने इस बात का विरोध किया है कि समाचार और सोशल मीडिया में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में दिखाने वाली तस्वीरों और वीडियो का मतलब यह है कि उन्हें उन सेवाओं में अपने पुरूष सहकर्मियों के समान अधिकार प्राप्त हैं।

यूक्रेन की महिला सैनिकों को अभी भी कमांडरों और साथी सैनिकों से उनकी प्रतिबद्धता और क्षमताओं, पदोन्नति और कैरियर के विकास में बाधाओं के साथ-साथ व्यावहारिक कठिनाइयों जैसे वर्दी, शरीर कवच और फिट होने वाले जूते आदि मामलों में कठिनाइयों को दूर करना है। महिलाएं यौन हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। कई यूक्रेनी महिला लड़ाकों ने पत्रकारों के साथ साक्षात्कार में उल्लेख किया कि महिला सैनिकों को किसी भी तरह से कैद से बचना चाहिए और वे रूसियों द्वारा पकड़े जाने के बजाय मरने के लिए तैयार हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बजट पर किसानों ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। इस बजट के लिए मंत्रीमंडल के सभी सदस्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की प्रशंसा की। केंद्र सरकार के मंत्री बजट की सराहना करते थक नहीं रहे हैं। वहीं ज्यादातर किसानों ने इस बजट को अपने लिए छलावा बताया है। इस बजट में मोदी सरकार ने सभी वर्गो का ध्यान रखा है। किसानों के लिए इस बजट में कहा गया कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि–स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की भी बात कही है। किसान केंद्र सरकार के इस बजट से खुश नहीं दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि मोदी सरकार का ये बजट भी किसानों के हक में नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए था कि खाद बीज और खेती से जुड़ी अन्य वस्तुए सस्ती करनी चाहिए थी। ऐसा तो कुछ इस बजट में नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि डेयरी पशुपालन व मस्तस्य पालन के लिए ऋण बढ़ाया है। लेकिन आजकल डेयरी के काम में काफी नुकसान हो रहा है। मतस्य पालन के क्षेत्र में भी नुकसान ही हो रहा है। कुल मिलाकर किसान पिस रहे हैं। लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। सरकार को चाहिए था कि ऐसा बजट लाए जिससे किसानों को ऋण लेना ही न पड़े। किसानों ने बताया कि कुल मिलाकर मोदी सरकार का यह बजट भी पिछले सभी बजट की ही तरह से रहा जिसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से काम करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका।

3 पार्षद और 7 निगम अधिकारियों को 3–3 साल की सजा

इंदौर (ईएमएस)। विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता की न्यायालय ने इंदौर नगर निगम के 3 पूर्व पार्षद और 7 अधिकारियों को 3–3 साल की सजा सुनाई है। जिन निगम अधिकारियों को सजा सुनाई गई है। वह सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कुछ आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। 20 साल पहले इंदौर के मेघदूत उपवन घोटाले में भ्रष्टाचार निवारण मामलों मैं भ्रष्टाचार के आरोप में 3 पूर्व पार्षद और 7 निगम के अधिकारियों को दोषी पाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद 100000 की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर न्यायालय से आरोपियों को जमानत दी गई है।

जिनको सजा मिली

एमआईसी के पूर्व सदस्य सूरज कैरो पूर्व पार्षद कैलाश यादव और राजेंद्र सोनीनगर निगम के अधिकारी सहायक नगर सिलपगय सुरेश कुमार जैनतत्कालीन उद्यान निरीक्षक अमानुल्लाह खान ठेकेदार केशव पंडित तत्कालीन सीनियर ऑडिटर विद्यानिधि श्रीवास्तव तत्कालीन सहायक संचालक ऋषि प्रसाद गौतम तत्कालीन कार्यपालन यंत्री अशोक बैजल तथा तत्कालीन नगर शिल्पग्य जगदीश डगांवकर शामिल है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष छोटू शुक्ला ने 2003 में लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। तत्कालीन महापौर परिषद के सदस्य और निगम अधिकारियों ने मेघदूत उपवन को विकसित करने के नाम पर कार्य योजना बनाकर ढाई करोड़ रुपए खर्च करना बताया है। इसमें से अधिकांश पैसा कागजों पर खर्च हुआ है। मेघदूत उपवन का निर्माण 80 के दशक में इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया था। कैलाश विजयवर्गीय महापौर बने तो आईडीए ने गार्डन नगर निगम को सौंप दिया था। इसके बाद नगर निगम ने ढाई करोड़ रुपए गार्डन के सौंदर्यीकरण के नाम पर कार्यों पर खर्च कर दिए। इसके बाद ठेका दे दिया। 2015 में लोकायुक्त पुलिस ने जांच कर चालान पेश किया था। सुनवाई के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।

आदिवासियों की जमीन खरीदने आदिवासी युवतियों से शादी

–पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी का चलन बढ़ा

रायपुर। छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमा के आसपास बने हुए बहुत सारे गांव में आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए गैर आदिवासी पुरुष आदिवासी युवतियों के साथ दूसरी शादी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर और बलरामपुर जिले में दर्जनों गांव और कस्बों के गैर आदिवासी सैकड़ों लोगों द्वारा आदिवासी युवतियों से शादी कर आदिवासियों की संपत्ति भी खरीद रहे हैं उन्हें चुनाव में भी लड़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जसपुर और बलरामपुर में राजस्व रिकॉर्ड में 3000 से अधिक ऐसे प्रकरण मिले हैं। जिसमें आदिवासी युवतियों के नाम पर आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर खरीदी गई है। इनके पति आदिवासी नहीं है। गैर आदिवासी समाज के लोग आदिवासी युवतियों से शादी कर आदिवासियों की जमीन और संपत्ति खरीदते हैं। इसके साथ ही अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में भी उतारते हैं। राजनीति से जुड़े एक नेता जी ने 4 शादियां कर उसमें से तीन पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारकर उन्हें पंच और सरपंच बना लिया है।

हाईकोर्ट के 2 चीफ जस्टिस तुरंत पदोन्नत करे सरकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कि कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अनुशंसा की है। सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 27 न्यायाधीश नियुक्त हैं। 7 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इन दोनों नामों के लिए कॉलेजियम के 6 सदस्य एकमत थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुशंसा कर सुप्रीम कोर्ट के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की अनुशंसा सरकार से की है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की वरीयता को लेकर भी सरकार द्वारा समय–समय पर जो देरी की जाती है। उससे सुप्रीम कोर्ट की वरीयता क्रम में और हाईकोर्ट की वरीयता क्रम में अंतर आ रहा है। इसको लेकर भी कॉलेजियम अब सजग हो गया है।

गवाह के बयान मातृभाषा में दर्ज किए जाएं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वह गवाह के बयानगवाह की भाषा है। उसी भाषा मैं बयान को दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायालय के रिकॉर्ड के लिए कोर्ट की भाषा में इसका अनुवाद किया जाना चाहिए। यदि गवाह कोर्ट की भाषा में या स्थानीय भाषा में गवाही देता हैतो इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवादित रूप में रिकॉर्ड में रखने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी भाषा में गवाह के बयान अनुवाद कर रखने की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह गवाही दर्ज करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के प्रावधानों का पालन करें। ट्रायल कोर्ट में गवाहों के बयान उनकी भाषा में दर्ज किए जाएं। न्यायालय यदि बयान को अनुवादित कराना चाहती हैतो उसमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही अनुवाद किया जाए।

जम्मू–कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण हिमस्खलन, चपेट में आकर पोलैंड के दो पर्यटकों की मौत

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर के बारामूला जिले में 'गुलमर्ग स्कीइंग रिज़ॉर्ट' के ऊंचाई वाले इलाके में बुधवार को एक भीषण हिमस्खलन हुआ। जम्मू–कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन की चपेट में आने से पोलैंड के दो पर्यटकों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बारामूला जिला पुलिस के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, हिमस्खलन गुलमर्ग में एक प्रसिद्ध स्की रिज़ॉर्ट अफरवत चोटी हापथखुद में हुआ। बारामूला पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि दो विदेशी नागरिक (स्की करने आए) और दो 'गाइड' के लापता होने की खबर थी। जिनकी अब मौत की खबर आ रही हैं। पुलिस ने बताया कि स्कींग कर रहे विदेशी और स्थानीय पर्यटक ढलान पर थे कि अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। पुलिस ने बताया कि अब तक कम से कम 19 विदेशियों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। पुलिस के अनुसार, पोलैंड के दो नागरिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

बजट ने ज्यादातर लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया: पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को दावा किया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये गये केंद्रीय बजट ने देश के ज्यादातर लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने एक बयान में कहा, ''वर्ष 2023-24 के लिए बजट और वित्त मंत्री का बजट भाषण यह प्रदर्शित करता है कि जनता, उसके जीवन, आजीविका तथा अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई से सरकार कितनी अनजान है।''

चिदंबरम ने दावा किया, ''वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जैसे शब्दों का कहीं उल्लेख नहीं किया। शुक्र है कि उन्होंने 'गरीब' शब्द का उल्लेख दो बार किया।'' उन्होंने कहा, ''मुझे यकीन है कि भारत के लोग इसका संज्ञान लेंगे कि सरकार को किन लोगों की चिंता है और किन लोगों की नहीं है।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की ओर से अनुमानित जीडीपी (वास्तविक मूल्यों पर आधारित) 232,14,703 करोड़ रुपये बताई गई थी और 11.1 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया गया था। वहीं, वर्ष 2022-23 के लिए 258,00,000 करोड़ रुपये की जीडीपी का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने कहा कि आज पेश किये गये बजट में सरकार ने 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान 273,07,751 करोड़ रुपये का लगाया है।

चिदंबरम ने कहा,''इसतरह, वास्तविक मूल्यों पर आधारित जीडीपी दोगुनी होनी चाहिए थी, जबकि वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) द्वारा और आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि जीडीपी की वृद्धि दर सात प्रतिशत रही। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।'' उन्होंने दावा किया, ''नयी कर व्यवस्था को अपनाने वालों के अलावा अन्य के लिए कर में कोई कमी नहीं दी गई है। अप्रत्यक्ष कर में कोई कमी नहीं की गई है। आतिर्कक जीएसटी (माल एवं सेवा कर) की दरों में कोई कमी नहीं की गई है। पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, उर्वरक की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। कई अधिभारों और उपकरों में कोई कमी नहीं की गई है।'' चिदंबरम ने दावा किया कि यह एक 'संवेदनहीन' बजट है, जिसमें देश के ज्यादातर लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने कहा कि ध्यान से विश्लेषण किया जाए, तो नयी कर व्यवस्था में भी लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति दी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 13 वर्षीय गर्भवती किशोरी को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की मंगलवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों का दल बुधवार को गर्भपात के लिए आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया करेगा। किशोरी और उसकी मां ने कहा कि पीड़िता गर्भपात कराना चाहती है जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इस अदालत का मानना है कि नाबालिग लड़की के जीवन उसकी शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उसके हित में होगा कि गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है जिसके मद्देनजर गर्भपात का खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वहन करेगा।

यूएस की राजकीय यात्रा पर जाएंगे नरेंद्र मोदी, जो बाइडन ने भेजा निमंत्रण, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे भारत के प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही रहे हैं और 1947 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी जारी रहे हैं। वर्तमान में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और अक्सर आतंकवाद का मुकाबला करने, पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर आपसी अविश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव जैसे मुद्दों पर दोनों साथ-साथ नजर आये हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट गयी थी तब से अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चला। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही अमेरिका का वर्चस्व काल आया। जब दुनिया दो गुटों में बटी थी तब भारत किसी भी गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्ष रहा लेकिन अमेरिका लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा जिसके कारण भारत रूस के करीब आया। 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को एक केंद्रीय संधि संगठन (ष्टश्वहञ्जह्र) सहयोगी बनाया। परिणामस्वरूप, भारत ने पाकिस्तान-संयुक्त राज्य संबंधों का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ के साथ रणनीतिक और सैन्य संबंधों को विकसित किया। 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शक्ति के खेल में शामिल होने से बचने के लिए भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य बन गया। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के लिए निक्सन प्रशासन के समर्थन ने 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक संबंधों को प्रभावित किया। 1990 के दशक में, भारतीय विदेश नीति एकध्रुवीय दुनिया के अनुकूल हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित हुए।

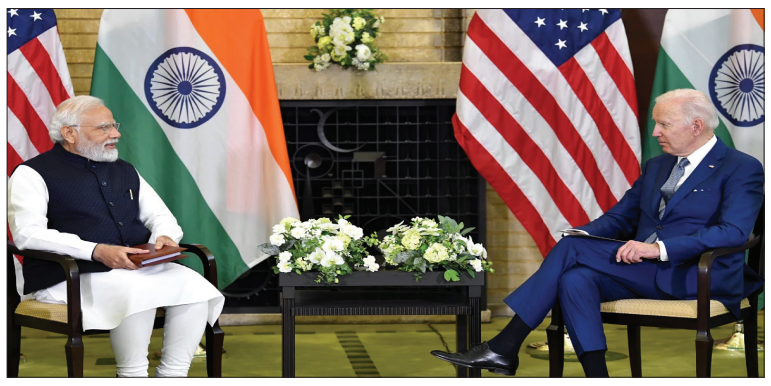

समाचार एजेंसी ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गर्मी में राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैद्धांतिक रूप से निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी की अपेक्षित यात्रा वर्तमान में लॉजिस्टिक प्लानिंग के शुरुआती चरण में है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने दोनों विश्व नेताओं के मिलने के लिए सुविधाजनक तारीखों को चयन करना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा कथित निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब भारत ने 20 देशों के समूह (जी-20) की अध्यक्षता संभाली है। भारत इस साल जी-20 से संबंधित कई कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। सितंबर में जी-20 का एक शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें राज्य के अन्य नेताओं के अलावा बाइडेन भी शामिल होंगे।

दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव : केजरीवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से साल 2023- 24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते ही इस पर हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1।75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया। उस में से मात्र 325 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास के लिए दिए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है उन्होंने एक और ट्वीट में कहा इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं। उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं। शिक्षा बजट घटाकर 2.64 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करना दुर्भाग्यपूर्ण। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2 प्रतिशत से 1.98 प्रतिशत करना हानिकारक इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पर तंज कसा है। उन्होंने निर्मला सीतारामन के अमृत काल वाले बयान पर निशाने साधते हुए कहा- न प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई ना रोजगार मिला न ही किसानों की एमएसपी तक बढ़ी। आप हमें बताइए देश में किसी आय दोगुनी हुई किसके लिए आया अमृतकाल? आम लोगों के लिए अमृत काल कब बरसेगा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पर तंज कसते हुए कहा निर्मला सीतारामन ने आपने बजट भाषण में कहा है कि अमृतकाल आ गया है लेकिन ताजा बजट से कितना अमृत बरसेगा देखना बाकी है? न किसानों की एमएसपी बढ़ी न नौजवानों को रोजगार मिला। ये पीएम मोदी का अमृत काल है। निर्मला सीतारामन कह रही हैं प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई मैं उनसे पूछता हूं कि ये आय किसकी बढ़ी है क्या आप इसका जवाब देंगी

मधुशाला में बने गोशाला! महिला अपराधों पर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए उमा भारती ने दी चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को शराब के सेवन से जोड़ने की मांग करने वाली भाजपा की दिग्गज नेता उमा भारती ने मध्यप्रदेश सरकार से शराब की दुकानों को गौशाला में बदलने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिग्गज नेता उमा भारती ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को गौशालाओं में बदलने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को शराब के सेवन से जोड़ने की मांग की। शनिवार दोपहर को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की राजधानी के अयोध्या नगर तिराहे में एक शराब की दुकान के पास स्थित एक मंदिर में पहुंचीं और घोषणा की कि वह 31 जनवरी तक वहीं रहेंगी, सरकार द्वारा नई शराब नीति की घोषणा की प्रतीक्षा कर रही हैं। भोपाल में एक मंदिर में अपने चार दिवसीय प्रवास को समाप्त करते हुए, भारती ने राज्य में नियंत्रित शराब नीति की अपनी मांग के समर्थन में 'मधुशाला में गौशाला' (शराब की दुकानों के स्थान पर गौशाला) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। मीडिया को संबोधित करते हुए, भाजपा के दिग्गज ने दावा किया कि भोपाल से लगभग 350 किमी दूर स्थित निवाड़ी जिले के ओरछा में प्रसिद्ध राम राजा सरकार मंदिर के पास स्थित एक शराब की दुकान अवैध थी। उन्होंने कहा, शराब नीति का इंतजार किए बिना मैं नियमों के विपरीत चल रही शराब की दुकानों को गौशालाओं में तब्दील करना शुरू करूंगी।

बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेंगे : ओ.पी. राजभर

बलिया (उत्तर प्रदेश) (एजेंसी)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को कहा कि वह महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। राजभर ने बुधवार को पीटीआई-को बताया कि उनकी दो दिन पहले शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि डेढ़ घंटे की यह मुलाकात सकारात्मक थी जिसमें उनकी ठाकरे से महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने दावा किया कि ठाकरे ने बीएमसी चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकरे की शिवसेना के साथ गठजोड़ करेंगे, राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना का आधार नहीं है। रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद के संबंध में राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा, ''सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौर्य जनाधार वाले नेता नहीं हैं। अगर वह जनाधार वाले नेता होते तो विधानसभाचुनाव नहीं हारते। उन्हें विधान परिषद के पिछले दरवाजे से सदन में नहीं जाना पड़ता।''

गौरतलब है कि सपा नेता मौर्य ने हाल ही में कथित तौर पर कहा था कि रामचरितमानस के कुछ दोहों में समाज के एक बड़े वर्ग का जाति के आधार पर 'अपमान' किया गया है और इन पर 'प्रतिबंध' लगा देना चाहिए। राजभर ने कहा कि अपने शासनकाल में पिछड़े वर्ग के हितों और पदोन्नति में आरक्षण की अवहेलना करने वाली समाजवादी पार्टी को अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन नहीं मिलेगा।

2024 के लिए गेम चेंजर साबित होगा कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने राज्य में चला 'तुलु कार्ड'

नई दिल्ली। (एजेंसी)। कर्नाटक समेत पांच राज्यों के होने वाले को लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। चार उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ ही कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले सेमीफाइनल की तरह भी काम करेगा। लगभग उत्तर पूर्व पहले ही जीत चुकी बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप की योजना बना रही है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक के लिए भारतीय जनता पार्टी एक आरामदायक स्थिति में दिख रही है। हालांकि, इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और शायद इसीलिए उन्होंने अपना इक्का-तुलु कार्ड खेल दिया है।

तुलू को मिलेगा आधिकारिक भाषा का दर्जा?

30 जनवरी को कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ने तुलु को आधिकारिक भाषा बनाए जाने की संभावना का आकलन करने के लिए एक पैनल के गठन की घोषणा की। कर्नाटक की भाजपा सरकार तुलु को राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में काम कर रही है। समिति की अध्यक्षता अल्वा के एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहन अल्वा करेंगे और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी का यह पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले 2008 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कदम उठाए थे, हालांकि, पहल वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच सकी।

कांग्रेस ने भाजपा के आगे हथियार डाल दिए

लगातार गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस राज्य में अपना जनाधार खोती जा रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के मास्टरस्ट्रोक के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। भाजपा सरकार द्वारा लिए गए किसी भी फैसले की अतार्किक आलोचना करने के लिए जानी जाने वाली कांग्रेस ने इस कदम का स्वागत किया है। कर्नाटक के तुलु बेल्ट वाले तटीय क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रवक्ता लावण्या बल्लाल जैन के साथ सुनील कुमार की घोषणा का स्वागत किया है। भाजपा की पहल का समर्थन करते हुए जैन ने कहा कि भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में भी जोड़ा जाना चाहिए।

क्या है तुलु

तुलु भाषा द्रविड़ भाषाओं के समूह में से एक है जिसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ शामिल हैं और इसे सबसे पुराने में से एक माना जाता है। कई रिपोर्टों के अनुसार तुलु भाषा कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में लगभग 10 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में, तुलु मुख्य रूप से बोली जाती है और स्थानीय लोग इस क्षेत्र को तुलुनाडु कहते हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)